RNI Title Code: DELHIN/28720

An Initiative of OBSERVER DAWN

ऑब्जर्वर डॉन

दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका वर्ष - 6, अंक - 5, अगस्त 2022 ₹ 100



रॉकेट बनी ईडी

'5000 से ज्यादा केस दर्ज'

देश का अरबों रुपया वापस सरकारी खजाने में पहुंचा

राजनीति

10 मनोज झा के भाषण में ऐसा क्या है कि कुछ नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है

बीच बहस

20 चीन को 2030 तक पीछे छोड़ देगा भारत, तेजी से बढ़ रही है भारत की आबादी

विदेश

42 चीन के लिए ताइवान पर जीत आसान नहीं गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं 35 लाख ताइवानी

KW GROUP
for touching heights

KW Delhi 6

freedom shopping

Ultimate Shopping Destination

@ Raj Nagar Extension, Ghaziabad

Open Now



Investors Growth - Upto **649%** in Last 10 Years

Ready for Possession

Hand to Hand Registry | Rent Guarantee - 9 yrs

Property Starts
₹22 Lacs

Rent Guarantee
₹18.50 Lacs

83+
Brands Associated With Us

SMART SUPERSTORE | BIKANERVALA | THE Raymond SHOP | max | Domino's

Call: 74-28-61-00-89

Site Office: KWDelhi6, Main Road (NH-58) Raj Nagar Extension, Ghaziabad, U.P. | **Corp. Office:** B-97, Sector-63, Noida, U.P.
Tel: 0120-4804747, | **Website:** www.kwdelhi6.com, kwgroup.in | **Email:** sales@kwgroup.in

Download the Observer Dawn App Today!

Get Latest News of the Hour, Anytime, Anywhere!

OBSERVER DAWN

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store



@observerdawn @observerdawngroup @observerdawn @observer-dawn @observerdawn

An Initiative of OBSERVER DAWN

ऑब्जर्वर डॉन

मासिक पत्रिका का ग्राहक बनने का सुनहरा अवसर

कॉल करें 0120-4804780

.....और अपनी पत्रिका सबस्क्राइब कराएं।

अपनी मनपसंद पत्रिका ऑब्जर्वर डॉन अपने घर पर प्राप्त करने के लिए हमें सूचित करें। हम सुनिश्चित करेंगे कि पत्रिका आप तक जरूर पहुंचे









हां मैं निम्नांकित पत्रिकाओं का ग्राहक बनना पसंद करूंगा/करूंगी

पत्रिका	आवृति	मूल्य	1 साल के लिए				2 साल के लिए				3 साल के लिए			
			वास्तविक मूल्य	आप देंगे	आप पायेंगे	निशान	वास्तविक मूल्य	आप देंगे	आप पायेंगे	निशान	वास्तविक मूल्य	आप देंगे	आप पायेंगे	निशान
ऑब्जर्वर डॉन (केवल हिन्दी)	मासिक	₹100	₹1200	₹1000	2 महीना मुफ्त	☐	₹2400	₹2000	4 महीना मुफ्त	☐	₹3600	₹3000	6 महीने मुफ्त	☐
ऑब्जर्वर डॉन (केवल अंग्रेजी)	मासिक	₹300	₹3600	₹3000	2 महीना मुफ्त	☐	₹7200	₹6000	4 महीना मुफ्त	☐	₹10800	₹9000	6 महीने मुफ्त	☐

ऑब्जर्वर डॉन इन 2 भाषाओं में उपलब्ध है कृपया विकल्प पर निशान लगायें

कुल राशि ₹ में

हिन्दी ☐ अंग्रेजी ☐

संलग्न चेक/डिमांड ड्राफ्ट नं. ☐☐☐☐☐☐ दिनांक ☐☐☐☐☐☐ आहरित बैंक (बैंक का नाम).....

कृपया अपना नाम और पता चेक/डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिखें।

Observer Dawn Media & Entertainment Pvt Ltd. के पक्ष में देय है

सब्सक्राइव करने के लिऐ हमें observerdawn1@gmail.com पर मेल करें

नाम.....

पता.....

.....राज्य.....पिन.....

फोन.....ई–मेल.....

कृपया इस ऑर्डर फार्म को भर कर ऑब्जर्वर डॉन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड बी–97, सैक्टर–63, नोएडा पर भेजें

* नियम और शर्तें: पत्रिका का मूल्य और ऑफर सिर्फ भारत में लागू। कृपया पत्रिका की पहली प्रति डाक या कूरियर के माध्यम से मंगाने के लिए चार से छह सप्ताह का समय दें। अगर आप पत्रिका कूरियर से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सालाना 240 रुपए अलग से लगेगा। पूछताछ के लिए 0120–4804780 पर डायल करें। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा

Email : observerdawn1@gmail.com

OBSERVER DAWN
Power of Thoughts

सम्पादक
डॉ हरिओम त्यागी

न्यूज एडिटर
रवीन्द्र कुमार

संयुक्त सम्पादक
दिनेश गौर

सलाहकार सम्पादक
राकेश पुरोहित

कंटेंट राइटर
सृष्टि नागर

चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ
अनूप कुमार

सेल्स एण्ड मीडिया मार्केटिंग

उमाकान्त मिश्रा - नेशनल हेड (मार्केटिंग)

लोकेश शर्मा - चीफ मैनेजर

संजीव कुमार सिंह - सकुर्लेशन ऑफिसर

पृष्ठ संयोजन

कला निर्देशक
अनिल कुमार

चित्र संयोजन

छायाकार
सचिन कुमार • लव गौर

ऑब्जर्वर डॉन

प्रकाशक एवं मुद्रक हरिओम त्यागी द्वारा मॉडेस्ट प्रिंट पैक प्रा. लि., सी-52, डीडीए शेड्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित एवं एस-507-ए, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, नई दिल्ली-110092 से प्रकाशित।

कॉरपोरेट ऑफिस
बी - 97, सैक्टर - 63, नोएडा,
गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
दूरभाष : 0120 - 4804747
email : editor@observerdawn.com
email : info@observerdawn.com
www.observerdawn.com

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं समाचारों के किसी भाग का बिना अनुमति लिए किसी भी विधा में पूर्ण या आंशिक उपयोग अवैधानिक है। विवाद की स्थिति में समस्त विवादों का निपटारा दिल्ली / नई दिल्ली के सक्षम न्यायालय में ही किया जाएगा।

संपादक की कलम से....



बिहार में बड़ा गेम होने से पहले ही नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी

बिहार की राजनीति में बड़ा गेम होता इससे पहले ही नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति की शतरंज पर एक तीर से तीन शिकार कर डाले जिसके बाद बीजेपी बिहार में औंधे मुंह जा गिरी।

बीजेपी ने कहां तो यह सोचा था कि आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर वह महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार को जीत लेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने उससे पहले आरसीपी सिंह के भ्रष्टाचार के सबूत देकर न सिर्फ आरसीपी सिंह पर शिकंजा कसा बल्कि उनका बंगला भी खाली करवाकर उनका एक तरह से राजनीतिक करियर भी खत्म कर दिया। दूसरी ओर इस कदम से बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर नीतीश कुमार रोक लगाने में कामयाब तो हुए ही साथ ही तीसरा सबसे बड़ा कदम उनका 2024 के लिए एक तरह से विपक्ष को खड़ा कर देना का भी रहा। अब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर बिहार में सत्ता पर काबिज होने का फैसला कर लिया है।

इससे पहले नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश भी गृह मंत्री अमित शाह ने की, लेकिन पिछले दिनों बिहार में जेपी नड्डा के दौरे के दौरान उनके द्वारा दिये गए भाषण, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुभ गए। जेपी नड्डा ने साफ कहा कि बिहार में सिर्फ बीजेपी ही विकल्प है। क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व अब खत्म हो चला है और जो 20 साल पुरानी पार्टी के सदस्य रहे आज वह बीजेपी के साथ है। यह बात सीएम नीतीश कुमार को इस तरह नागवार गुजरी कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी नीतीश कुमार को समझा नहीं पायी और ऑपरेशन लोटस के शुरू होने से पहले ही नीतीश कुमार ने इस ऑपरेशन को अपनी राजनीतिक सूझबूझ से बूट तले रौंद दिया।

अब आपको बिहार की सत्ता के समीकरण को भी बताते चले। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से आरजेडी के खाते में 79 बीजेपी के खाते 77 और जेडीयू के खाते में 45 सीटें हैं। इसी तरह से कांग्रेस के खाते में 19 लेफ्ट के खाते में 16 हम के हिस्से में 4 और एक निर्दलीय उम्मीदवार है वहीं, एक सीट खाली भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति बहुत कुछ ऐसी है कि बगैर किसी मेल मिलाप के किसी भी पार्टी की सरकार बिहार में बनती नहीं दिखती।

पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में घुटन महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार की सत्ता पर सात बार कब्जा जमाया है और इसबार आठवीं बार सूबे के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे वह नीतीश कुमार राजनीति में ऐसी पैंठ रखते हैं कि सत्ता बिहार में या केन्द्र में किसी की भी रही हो, लेकिन नीतीश पिछले तीन दशक से सत्ता की धुरी बने रहे।

बिहार में जब लालू प्रसाद यादब की सरकार थी तब केन्द्र में यूपीए सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे। बिहार की बात की जाए तो मौजूदा समय में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद अब जेडीयू कांग्रेस, आरजेडी के साथ सरकार बना रही है। ऐसे में यह तय है कि बिहार में अब नये राजनीतिक समीकरण तैयार होंगे और कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति सत्ता की चाबी का निर्धारण भी करती है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलता है और क्या कुछ होता है। फिलहाल बिहार के 8वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमारी ओर से बधाई।



डॉ. हरिओम त्यागी
संपादकः ऑब्जर्वर डॉन

Connect with Dr. Hariom Tyagi

@harityagi2003 | @harityagi

इस अंक में

08 **रक्षा बंधन**
भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना



10 **राजनीति**
मनोज झा के भाषण में ऐसा क्या है कि कुछ नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है



12 **कबर स्टोरी**
रॉकेट बनी ईडी – '5000 से ज्यादा केस दर्ज', देश का अरबों रुपया वापस सरकारी खजाने में पहुंचा



20 **बीच बहस**
चीन को 2030 तक पीछे छोड़ देगा भारत, तेजी से बढ़ रही है भारत की आबादी



24 **स्वास्थ्य**
वर्क फॉर्म होम से बढ़ रही है टाइप टू डायबिटीज की समस्या

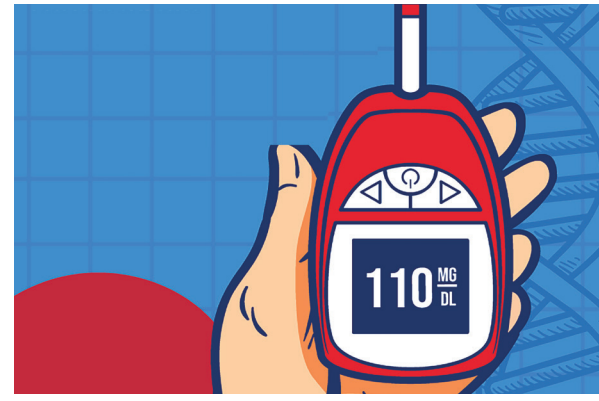

28 **अर्थजगत**
फ्हकने ब्याज दरें 0.50% बढ़ाईः लोन महंगे होंगे, 20 साल वाले 30 लाख के होम लोन की एटक करीब 900 रु. ज्यादा होगी



इस अंक में

32 **समाज**
लेकिन ईरान में इससे आजादी के लिए सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं भारत में हिजाब पर बवाल



36 **देश दुनिया**
कैसे एक खास मिसाइल R9X हेलफायर से मारा गया अल जवाहिरी



38 **पर्यावरण**
स्मार्ट सिटी तो बना ली लेकिन स्मार्ट सिटी से निकलने वाले कूड़े का क्या इंतजाम है



42 **विदेश**
चीन के लिए ताइवान पर जीत आसान नहीं गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं 35 लाख ताइवानी



46 **अलविदा**
अलविदा शिंजो आबे, आप बहुत याद आएंगे



48 **इतिहास**
काकोरी कांड : जिसने देश में क्रांतिकारियों के प्रति जनता का नजरिया बदल दिया था



भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना



हिन्दू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षा बंधन या कहें कि राखी का त्यौहार मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार यह पर्व 11 अगस्त 2022 को मनाया जाएगा। आईये जानते हैं इस त्योहार को मनाए जाने संबंधी 10 पौराणिक मान्यताएं।



रक्षा बंधन का त्योहार भाई बहन का बेहद ही पवित्र त्योहार है। इस दिन बहने भाई की कलई पर रक्षा सुत्र बांधकर एक तरफ भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं तो वहीं भाई भी आजीवन बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं।

यह एक ऐसा त्योहार है जिसे लगभग पूरे भारत में बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार ऐसा है कि इसे न सिर्फ हिन्दु ही मनाते हैं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी इस त्योहार में शामिल होकर इस त्योहार की पवित्रता को बढ़ाते हैं।

रक्षा बंधन का इतिहास

रंक्षा बंधन का त्योहार भारतीय घरों में खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को गरीब से लेकर अमीर तक सभी मनाते हैं। जैसे सभी त्योहारों का इतिहास होता है ऐसे रक्षा बंधन का भी अपना इतिहास है।

सम्राट सिकंदर और सम्राट पुरु

रक्षा बंधन का त्योहार सबसे पहले सन 300 इउ मनाया गया था। उस समय अलेक्जेंडर यानी सिकंजर भारत को जीतने के लिए अपनी सारी सैना लेकर यहां आया था और यहां सम्राट पुरु का काफी नाम था। अलेक्जेंडर ने कभी किसी से मात नहीं खाई लेकिन सम्राट पुरु की सैना के साथ लड़ने में उन्हें परेशानी हो रही थी। लेकिन जब अलेक्जेंडर की वाइफ को रक्षा बंधन के बारे में पता चला तो उसने सम्राट पुरु के लिए राखी भिजवाई। उनका राखी भिजवाने का मकसद यह था कि जिससे सम्राट पुरु उनके पति अलेक्जेंडर को जान से न मार दें। इसलिए पुरु ने अलेक्जेंडर की पत्नी की भेजी हुई राखी का रिश्ता निभाया और सिकंदर को नहीं मारा।

रक्षा बंधन का पौराणिक महत्व

भविष्य पुराण में लिखा है कि सबसे पहले इन्द्र की पत्नी शचि ने वृत्तसुर से युद्ध में इन्द्र की रक्षा के लिए रक्षा सूक्ष बांधा था इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो

उसकी कलाई पर कलाया, मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्रीहरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी।

राजा बलि और माँ लक्ष्मी

भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हरा कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्राह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गये। हालाँकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुण्ठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बाँध कर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उसके महल मे रहेंगे। बलि ने ये बात मान ली और साथ ही माँ लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में भी स्वीकारा।

संतोषी माँ सम्बंधित मिथक

भगवान विष्णु के दो पुत्र हुए शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों को एक बहन की कमी बहुत खलती थी, क्यों की बहन के बिना वे लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन दोनों भाइयों ने भगवान गणेश से एक बहन की मांग की। कुछ समय के बाद भगवान नारद ने भी गणेश को पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए और उन्होंने एक पुत्री की कामना की। भगवान गणेश की दो पत्नियों रिद्धि और सिद्धि, की दिव्य ज्योति से माँ संतोषी का अविर्भाव हुआ। इसके बाद माँ संतोषी के साथ शुभ लाभ रक्षाबंधन मना सके। संतोषी माता व्रत कथा एवं पूजा विधि यहाँ पढ़ें।

कृष्ण और द्रौपदी सम्बंधित मिथक

महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ मे राखी बाँधी थी। इसी युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर सुरक्षा के लिए राखी बाँधी।

कृष्ण और द्रौपदी की कहानी

जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा था तो उनके हाथ खून में सन गए थे। फिर द्रौपदी नें अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी के हाथ में बांध दिया था। जिसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को मुसीबत के समय सहायता करने का वचन दिया।

महाभारत में राखी

माना जाता है कि जब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा कि वह सारे संकटों को कैसे पार कर सकता है, तो कृष्ण जी ने उन्हें रक्षा बंधन का त्योहार बनाने की सलाह दी।

यम और यमुना सम्बंधित मिथक

एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार, मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गये, तो यमुना दुखी हुई और माँ गंगा से इस बारे में बात की। गंगा ने यह सुचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इस पर यम युमना से मिलने आये। यम को देख कर यमुना बहुत खुश हुईं और उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन भी बनायीं। यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वे मनचाहा वरदान मांग सकती हैं। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान माँगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आयें। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गद गद हो गए और यमुना को अमरत्व का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षा बंधन के हवाले से याद किया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षा बंधन दो शब्दों को मिलाकर बनता है, रक्षा और बंधन। जिसका मतलब एक ऐसा बंधन जो रक्षा करता हो। रक्षा बंधन भाई-बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षा बंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशिया लेकर आता है। इसके अलावा यह त्योहार भाईयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए।

रंक्षा बंधन का त्योहार भारतीय घरों में खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को गरीब से लेकर अमीर तक सभी मनाते हैं। जैसे सभी त्योहारों का इतिहास होता है ऐसे रक्षा बंधन का भी अपना इतिहास है।

मनोज झा के भाषण में ऐसा क्या है कि कुछ नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है

मॉनसून सत्र में विपक्ष के नेता मनोज झा का भाषण इन दिनों सुर्खियों में है। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही इस वीडियो को लेकर राजनीतिक गलियारों में फ्रीबीज या मुफ्तखोरी शब्द के इस्तेमाल पर बैन पर लगाने की मांग मनोज झा के द्वारा की जा रही है। मनोज झा का कहना है कि मुफ्त बिजली, पानी देना वेलफेयर स्टेट का काम है। लेकिन सत्ताधारी नेता फ्रीबीज जनता को देकर इलेक्शन तो जीतना चाहते ही है साथ ही इस शब्द का इस्तेमाल भी बंद नहीं करना चाहते। क्या है पूरा मामला पढ़िये।

- रवीन्द्र कुमार



मनोज झा आरजेडी से सांसद हैं। लोक कल्याणकारी मुद्दों को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहते है। मनोज झा का नाम ऐसे नेताओं में भी शामिल है जो जनता के मुद्दों के साथ राजनीति मुद्दों को भी गंभीरता से उठाते हैं। संसद से लेकर आम जनता के बीच मनोज झा एक इंटलेक्यूअल और ऐसे नेता हैं जिनकी बात संसद में भी मानी जाती है और आम जनता भी अपनी सहमति जताती है।

इस बार के मॉनसून सत्र में मनोज झा का एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में वह फ्रीबीज को लेकर सरकार पर एक तरफ से निशाना साधते हैं तो दूसरी ओर से निवेदन भी करते हैं।

मनोज झा कहते हैं कि फ्रीबीज शब्द को बैन किया जाना चाहिए। असल में मनोज झा मानते हैं मुफ्त बिजली, पानी, टीवी, स्कूटी देना वेलफेयर स्टेट का काम है।

वह कहते हैं, मुफ्तखोरी शब्द से देश के जरूरतमंद लोगों का तिरस्कार हो रहा है। फ्रीबीज देकर सरकार देश के लोगों के ऊपर कोई अहसान नहीं करती है। फ्रीबीज लोगों का अधिकार है। क्योंकि वह टैक्स देते हैं। टैक्स से देश और सरकार चलती है। साथ ही फ्रीबीज से अगर बजट पर फर्क नहीं पड़ता तो उसे देने में क्यों गुरेज होना चाहिए। और अगर नेता इस फ्रीबीज का इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए करें तो यह एक गलत परंपरा है। इस परंपरा को बंद किया जाना चाहिए। साथ ही फ्रीबीज राज्य की सरकारें अपने अपने राज्य की आवश्यकता के अनुसार प्रदान करें।

लेकिन एक तरफ फ्रीबीज शब्द का इस्तेमाल बंद करने और दूसरी ओर फ्रीबीज को जारी करने के बीच मनोज झा अपने ही दिये सुझाव के बीच फंसते नजर आए। क्योंकि अगर गौर से इस मुद्दे को देखे तो यह मुद्दा इतना उलझा हुआ है कि देश का कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सीधे तौर पर जबाव देने को राजी नही है। क्योंकि मौजूदा समय में फ्रीबीज पर कई राज्यों की सरकारे हाल ही में बनी है।

इस फेहरिस्त में आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा उदहारण है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिजली पानी फ्री देने का वायदा किया। आम आदमी पार्टी ने इस वायदे को निभाया भी जिसके बाद पंजाब में फ्री बिजली,पानी और पंजाब की छात्राओं को हर महीने आर्थिक सहायता के साथ मुफ्त शिक्षा तक की बात आम आदमी पार्टी ने की थी।

पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब भी रही। अब मनोज झा यह भी कहते हैं कि लोककल्याणकारी राज्य होने के नाते ये सरकारों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए मुफ्त शब्द इस्तेमाल न किया जाए। वो कहते हैं - ये लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास है। मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की ये दवाई.. ये क्या चल रहा है। मैंने कहा था आप वेलफेयर स्टेट हैं, अब तक, थैंकफुली। चूंकि आप वेलफेयर स्टेट हैं इसलिए मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। आप एक बड़ी आबादी को अपमानित करते हैं। नागरिकों के अपमान का अधिकार आपको नहीं है। आप देते क्या हैं - अनाज, वैक्सीन। ये आपका उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारें भी ऐसा कर रही हैं। करोड़ों के इश्तेहार छपवाकर बताया जा रहा है कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं।

अब संसद में मुफ्त शब्द के इस्तेमाल को बंद करने की मांग जायज है या नाजायज है, यह तो अभी तय नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि भारत का संविधान लोकल्याणकारी राज्य की बात करता है।

वहीं, दूसरी ओर अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुआई वाली पीठ ने इसे सीरियस मामला बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही सुझाव भी दिया है कि इसको लेकर वित्त आयोग सिफारिश कर सकती है। आप पूछेंगे इतनी चिंता क्यों है? तो इसलिए कि मुफ्तखोरी का लालच देकर चुनाव जीतने के चक्कर में राज्यों पर आज 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है।

और चलिए अब आपको संविधान के उन नीति निर्देशक तत्वों की जानकारी भी यहां दे देते हैं जिसमें वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की गयी है।

- अनुच्छेद 38- राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

- अनुच्छेद 39 -राज्य विशेष रूप से इन नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा
- सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार।
- भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिये व्यवस्थित करना।
- कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना।
- पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन।
- श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा
- बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना।

नीति निर्देशक तत्वों में हालांकि यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जनता को मुफ्त बिजली, पानी दी जाए लेकिन साथ ही यह भी परिभाषित किया गया है कि देश के हर एक व्यक्ति को पर्याप्त साधन का अधिकार मिलना चाहिए। और इसी में फ्रीबीज का मूल तत्व भी छुपा है।

सरकार ने इसी के चलते देश में कोविड-19 महामारी के दौरान मुफ्त वैक्सीन और अनाज देश के लोगों को दिया। ये जरूरतमंदों के लिए ही था। वहीं, मौजूदा समय में देश में सामाजिक-आर्थिक-राजनीति न्याय के लिए आरक्षण के अलावा कई तरह की योजनाएं तो चल ही रही हैं।

पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब भी रही। अब मनोज झा यह भी कहते हैं कि लोककल्याणकारी राज्य होने के नाते ये सरकारों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए मुफ्त शब्द इस्तेमाल न किया जाए। वो कहते हैं - ये लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास है।

फ्रीबीज का सबसे बड़ा नुकसान क्या है?

फ्रीबीज का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह मुफ्तखोरी की आदत लगा देता है। सरकार के द्वारा मिलने वाली फ्रीबीज धीरे-धीरे लोगों को आलसी और कामचोर बनाती है। देश के विकास पर भी फ्रीबीज का असर पड़ता है। फ्रीबीज धीरे-धीरे सरकार की जेब खाली करता है जिसका खामियाजा देश के लोगों को ही आगे चलकर भुगतना पड़ता है।

हालांकि फ्रीबीज कुछ समय के लिए गलत भी नहीं है लेकिन यह उसी समय में दिया जाना चाहिए जब इसकी आवश्यकता हो।

देश के कई राज्य कर्ज में डूबे हैं, कैसे कामयाब होगा फ्रीबीज?

फ्रीबीज बेशक आज के समय सबसे बड़ी बहस का कारण बना हुआ है। खजाना भरा हो तो मान सकते हैं कि फ्री में कुछ जनता जनार्दन को दे दिया जाए। सच्चाई तो उलट है। हमारे कई राज्यों की वित्तीय हालत नाजुक है। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक राज्य सरकार तय सीमा से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकते। रिजर्व बैंक ने तय किया है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट और जीडपी का अनुपात तीन ये इससे ज्यादा हो जाए तो मान लीजिए संकट गहरा है। इस साल की रिपोर्ट में अपने 10 राज्यों की हालत खराब है। पंजाब तो कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेता है। इसकी जीडीपी के 53 परसेंट से ज्यादा इसका कर्ज है। बिहार-झारखंड-आंध्र प्रदेश की हालत भी 35 परसेंट के आस-पास रेड जोन में है। ऐसी हालत में भला कोई नेता मुफ्तखोरी को वेलफेयर बताकर चुप रहने की बात कैसे कर सकता है?



रॉकेट बनी ईडी

'5000 से ज्यादा केस दर्ज'

देश का अरबों रुपया वापस सरकारी खजाने में पहुंचा

देश में ईडी पिछले पांच साल में सबसे ताकतवर एजेंसी के रूप में उभर कर सामने आयी है। अरबों रुपये की संपत्ति और धन ईडी ने पिछले पांच साल में जब्त किया है। देश छोड़ चुके अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर देश का पैसा वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। ईडी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं बावजूद इसके ईडी देश से भ्रष्टाचार की जड़ों को तेजी से काट रही है। आईये जानते हैं ईडी कैसे काम करती है और इसकी स्थापना का मकसद क्या था। साथ ही जानेंगे कि आखिर ईडी से भ्रष्ट नेता, व्यवसाती और अधिकारी क्यों खौफ खाते हैं।

-ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED विभाग की लगातार कार्रवाई से मौजूदा दौर में भ्रष्टाचारी थर-थर कांप रहे हैं। भ्रष्टाचार खुलने के साथ ही जब उनकी तिजोरियों से काला और गैन कानूनी धन बाहर निकल रहा है। भ्रष्टाचारी जेल की हवा खा रहे हैं।

पिछले आठ साल से ईडी की जांच का दायरा भी बड़ा। पहले बड़े-बड़े घोटालों की छानबीन या छापेमारी में हर जगह CBI ही नजर आती थी। लेकिन CBI पिछले 4 वर्षों में बैकग्राउंड में चली गई है और उसकी जगह ED ने ले ली है।

पड़ताल में सामने आया कि पिछले 8 वर्षों में एऊ की कार्रवाई में पांच से छह गुना का उछाल दर्ज किया गया है। हमने पड़ताल की कि किन वजहों से ED ने CBI को पछाड़ दिया। आइए आपको बताते हैं।

मोदी सरकार के 8 साल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई में तेजी आई है। ED की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 3,555 केस दर्ज किए और 99 हजार 355 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की।

मोदी सरकार के 8 साल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई में तेजी आई है। ED की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 3,555 केस दर्ज किए और 99 हजार 355 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की।

अगर पिछली यूपीए सरकार की बात करें तो 9 साल यानी जुलाई 2005 से मार्च 2014 तक 1,867 केस दर्ज किए गए। यूपीए सरकार में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 4,156 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 महीनों में 7,833 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है और 785 नए केस दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा यूपीए सरकार के नौ साल के मुकाबले 88 प्रतिशत तक ज्यादा है। अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक देश में मनी लॉन्ड्रिंग के कुल 395 केस दर्ज हुए थे और 8,989.26 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई थी।

देश में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में लागू हुआ था। तब से मार्च 2022 तक कुल 5,422 केस दर्ज हो चुके हैं और 1.04 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा संपत्ति अटैच की जा चुकी है। इन मामलों में कुल 400 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 25 दोषी ठहराया गया है।

बीजेपी सरकार के 8 साल में ही 2,974 छापे पड़े

यूपीए के 9 साल में ईडी ने सिर्फ 112 छापे मारे थे, जबकि एनडीए के 8 साल में ही 2,974 छापे पड़े हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में केंद्र ने बताया कि 2004 से 2013-14 के बीच ईडी ने 112 छापे मारे थे। वहीं, अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 2,974 छापे मारे गए।

9 राज्यों ने CBI की एंट्री बैन की

कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर रहे IPS राजीव कुमार के समर्थन में CM ममता बनर्जी ने न केवल धरना प्रदर्शन किया, बल्कि CBI की एंट्री राज्य में बैन करवा दी। इसके बाद आठ राज्यों ने ममता का अनुसरण किया।

कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर रहे IPS राजीव कुमार के समर्थन में CM ममता बनर्जी ने न केवल धरना प्रदर्शन किया, बल्कि CBI की एंट्री राज्य में बैन करवा दी। इसके बाद आठ राज्यों ने ममता का अनुसरण किया।

UPA शासनकाल तक CBI ही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती थी। केंद्र में BJP सरकार बनने के बाद जब इसी CBI ने गैर भाजपा शासित राज्यों में कार्रवाई करनी चाही तो ये राज्य लामबंद हो गए। देखते ही देखते राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मेघालय और मिजोरम की गैर भाजपा सरकारों ने एक के बाद एक अपने प्रदेश में CBI की एंट्री पर रोक लगा दी, मतलब बिना राज्य सरकार की इजाजत के CBI राज्य में जांच पड़ताल नहीं कर सकती। सबसे ताजा मेघालय राज्य ने CBI की एंट्री पर बैन लगाया है।

9 राज्यों में CBI की एंट्री बैन होने से मजबूरन केंद्र सरकार को आर्थिक अपराध की छानबीन से जुड़ी दूसरी बड़ी जांच एजेंसी यानी ED को सक्रिय करना पड़ा। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।

पिछले तीन से चार साल में ED का दायरा इतना अधिक बढ़ गया है कि हर बड़े घोटाले का खुलासा अब ED ही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी PMLA के तहत ED की गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती से जुड़ी शक्तियों को कायम रखा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि गिरफ्तारी के लिए ED को आधार बताना जरूरी नहीं है।

8 साल में 5 गुना बढ़े ED के एक्शन

पिछले 10 साल में ED ने विदेशी मुद्रा से जुड़े FEMA के तहत 24,893 मामले दर्ज किए। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के 3,985 मामले हैं। 2014-15 में FEMA के तहत दर्ज 915 मामले 2021-22 में बढ़ कर 5,313 हो गए। PMLA के तहत 2014-15 में 178 मामले दर्ज थे, जो 2021-22 में

बढ़ कर 1,180 हो गए। इस तरह 2014 से अब तक ED के दर्ज मामलों में पांच गुना का उछाल आया है। कुल मिलाकर 2014-15 में जहां 1,093 मामले दर्ज थे, वहीं 2021-22 में ये संख्या 5,493 हो गई है।

2019-20 के बाद और तेज हुई रफ्तार

FEMA के तहत 2018-19 में 2,659 मामले दर्ज किए थे, जो 2021-22 में बढ़कर 5,313 हो गए। इसी तरह, PMLA के तहत 2018-19 में दर्ज 195 मामले छह गुना बढ़कर 2021-22 में 1,180 हो गए।

ED बिना पेपर सिर्फ वजह बताकर कर सकती है अरेस्ट

ED को सुपर पावर बनाता है PMLA

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना था। यह कानून 2005 में अमल में आया। PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012 ने अपराधों की सूची का दायरा बढ़ाया। इनमें धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। इस संशोधन की बदौलत ED को विशेषाधिकार मिले। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसों की हेराफेरी है। यह अवैध तरीके से कमाई गई ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलने की तरकीब है। ये ज्यादातर मामले वित्तीय घोटाले के होते हैं। एक्ट की अनुसूची के भाग E में



शामिल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ED को राजनीतिक घोटालों पर कार्रवाई का अधिकार देता है।

ED के पास विशेष अधिकार

यह एक्ट प्रवर्तन निदेशालय को जब्ती, मुकदमा शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच और तलाशी की शक्ति देता है। आरोपी व्यक्ति पर जिम्मेदारी होती है कि वह अपने को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत दे।

ED पर आरोप लगता है कि इस एक्ट के कड़े प्रावधानों, जैसे कि जमानत की कड़ी शर्तें, गिरफ्तारी के आधारों की सूचना न देना, ECIR (FIR जैसी) कॉपी दिए बिना अरेस्टिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषा, जांच के दौरान आरोपी की ओर से दिए गए बयान ट्रायल में बतौर सबूत मानने आदि, का एजेंसी दुरुपयोग करती है।

PMLA के सेक्शन 3, 5, 18, 19, 24 और 45 ED को सुपरपावर बनाते हैं। आइए आपको उन सेक्शंस के बारे में एक-एक करके बताते हैं...

सेक्शन 3: यह सेक्शन दोषियों की बात करता है। इनमें हर ऐसा शख्स शामिल होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में लिप्त है।

सेक्शन 5: इसमें ऐसे लोगों की बात कही गई है जिनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसमें ये भी बताया गया है कि किन हालात में जब्ती नहीं की जा सकती है।

सेक्शन 18: ये तलाशी से संबंधित सेक्शन है। इसमें बताया गया है कि किन हालात में किसी की तलाशी ली जा सकती है।

सेक्शन 19: इसमें गिरफ्तारी के तौर-तरीकों के बारे में बताया गया है। कब और किन स्थितियों में गिरफ्तारी की जा सकती है, इसका भी जिक्र है।

सेक्शन 24: यह सेक्शन 'बर्डन ऑफ प्रूफ' की बात करता है। यह कहता है कि खुद को बेकसूर साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी व्यक्ति की होगी।

सेक्शन 42: इसमें बताया गया है कि एक्ट के तहत किन स्थितियों में हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।

ED की कार्रवाई पर हंगामा क्यों मचा

सियासी मामलों में ED की कार्रवाई से हंगामा मचा हुआ है। राजनीतिक दल अपने जनाधार का फायदा उठाने की भरसक कोशिश करते हैं। इसके लिए दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं और अपनी मशीनरी के जरिये मीडिया में खुद को विक्टिम की तरह पेश करते हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं।

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ से लेकर

FEMA के तहत 2018-19 में 2,659 मामले दर्ज किए थे, जो 2021-22 में बढ़कर 5,313 हो गए। इसी तरह, PMLA के तहत 2018-19 में दर्ज 195 मामले छह गुना बढ़कर 2021-22 में 1,180 हो गए।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के मंत्री तक की गिरफ्तारी ED कर रही है।

कांग्रेस, TMC सहित तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि भाजपा सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए ED का दुरुपयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को ED ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था।

ED के एक्शन से पहली बार एक साल के भीतर तीन राज्यों के चार प्रभावशाली मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है। इनमें महाराष्ट्र के तत्कालीन दो कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक शामिल हैं।

ED के एक्शन से तीन राज्यों के चार मंत्रियों को हुई जेल

ED के एक्शन से पहली बार एक साल के भीतर तीन राज्यों के चार प्रभावशाली मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है। इनमें महाराष्ट्र के तत्कालीन दो कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक शामिल हैं। नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए, जबकि देशमुख को ED ने एंटीलिया केस में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे द्वारा वसूले 4.7 करोड़ के मामले में की है। आरोप है कि ये रकम सचिन वझे ने मुंबई के कई रेस्तरां और बार ओनर्स से वसूले और देशमुख के निजी सचिव (PS) संजीव पलांडे और निजी सहायक (PA) कुंदन शिंदे को दिए थे। ये दोनों भी ED की गिरफ्त में हैं।

दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने 30 मई को गिरफ्तार किया था।

हाल में पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई है। ED के छापे में पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 27 करोड़ रुपये से अधिक कैश और 5 किलो सोने के जेवरात जब्त किए गए।

ED ने ही की सोनिया- राहुल से पूछताछ

नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने इसी साल जून में राहुल गांधी से कई बार पूछताछ की थी और अब जुलाई में वह इसी केस में सोनिया से पूछताछ कर रही है।



नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने इसी साल जून में राहुल गांधी से कई बार पूछताछ की थी और अब जुलाई में वह इसी केस में सोनिया से पूछताछ कर रही है। 1 नवंबर 2012 को BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज करवाया था। एक अगस्त 2014 को ED ने जांच अपने हाथ में ली और केस दर्ज किया। इस साल जून में राहुल गांधी से कई दिन तक ED अधिकारियों ने घंटों पूछताछ की। इस पर कांग्रेसियों ने संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन किया। पिछले दिनों कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी ED ने पूछताछ की। इस पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आंदोलन किया।

ED ने ममता को भी कराया खामोश

अर्पिता के घर से 500 और 2000 के नोटों के बंडल मिले। गिनती के बाद यह रकम 27.9 करोड़ बताई जा रही है। फरवरी 2019 में CBI टीम कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची तो ममता बनर्जी ने इसे मुद्दा बना दिया। ममता ने कार्रवाई के विरोध में रात में धरना दिया। इसके बाद CM ममता ने राज्य में CBI की एंट्री पर रोक लगा दी। उनके मंत्री पार्थ चटर्जी पर ED ने कार्रवाई की तो ममता ने चुप्पी साध रखी है।

राजस्थान पर भी ED की तलवार

राजस्थान REET पेपर लीक मामले में सियासी घमासान चल रहा है। गहलोत सरकार ने बैकफुट पर आकर शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। भाजपा ने 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। इससे पहले राजस्थान में फोन टैपिंग कांड की जांच CBI नहीं कर पाई। अब कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ED के जरिए केंद्रीय एजेंसी का राज्य में दखल हो सकता है।



कभी CBI से पीछे थी ED

CBI चार साल पहले तक देश के तमाम बड़े सियासी मामलों और घोटालों को टेकअप करती थी। इसके बाद ED की एंट्री होती थी। उदाहरण के लिए चारा घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला सहित तमाम बड़े चर्चित मामलों के अलावा मुलायम, मायावती, मधु कोड़ा से जुड़े केस भी हैं। राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है, जिससे वे ED के दखल को रोक सकें।

अर्पिता के घर से 500 और 2000 के नोटों के बंडल मिले। गिनती के बाद यह रकम 27.9 करोड़ बताई जा रही है। फरवरी 2019 में CBI टीम कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची

'टाइमिंग और सोशल मीडिया ने बदली धारणा'

ED के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि ED शुरू से ही एक्टिव है। एजेंसी की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। टाइमिंग और सोशल मीडिया ने परसेप्शन चेंज कर दिया है। झारखंड का माइनिंग स्कैम, कोयला घोटाला, जगन रेड्डी, बेलारी में रेड्डी बंधुओं का घोटाला, MP का व्यापम केस, पंजाब और हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाला, राजस्थान में आदर्श सोसाइटी घोटाला जैसे तमाम मामलों को ED ने पहले टेकअप किया था, लेकिन अब टाइमिंग कुछ ऐसी है, जैसे कि चुनाव या उसके आसपास के दौरान एक्शन होने से चर्चा ज्यादा होती है। जब भी एक्शन किसी राजनीतिक दल या नेता से जुड़ा होता है, तब शोर ज्यादा होता है। 2017 तक ED की स्ट्रेंथ एक हजार थी, जो बढ़कर 1600 हो गई है। स्थानीय कार्यालय खुलने से लोकल इनपुट भी आते हैं, जिससे ED के केस भी बढ़ रहे हैं।

नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉंड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ जारी है। सोनिया गांधी जब अपने

निवास से ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुईं तो उनके साथ राहुल गांधी भी थे। इससे पहले दूसरे दौर की पूछताछ हुई जहां सोनिया गांधी से करीब 6 घंटे में 50 से अधिक सवाल पूछे गए। ईडी जब सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी, तब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे।

संसद से लेकर सड़क तक इस विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसदों और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने अपने 75 सांसदों को हिरासत में लेने का दावा किया है। राहुल ने सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में पुलिस का राज है। पार्टी ने राजघाट पर गांधी समाधि पर सत्याग्रह की अनुमति नहीं देने के लिए सरकार पर भी हमला किया और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया।

भाजपा नेताओं पर जांच एजेंसियों की मेहरबानी

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, जब कांग्रेस में थे, तो लुईस बर्जर केस व शारदा घोटाले में, उन्हें ईडी और सीबीआई ने बुलाया या नहीं बुलाया। उसके बाद वे कांग्रेस से दौड़कर भाजपा में शामिल हो गए। चूंकि अब वे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं तो शारदा घोटाला व लुईस बर्जर केस कहां चले गए। ईडी के समन का क्या हुआ। ऐसे नेताओं के सामने विकल्प था कि वे भाजपा में आते हैं तो उनके सब गुनाह माफ हो जाएंगे। वे साफ सुथरे बनकर बाहर निकल जाते हैं।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, उन पर ईडी का केस दर्ज है या नहीं है। माकन ने कहा, येदियुरप्पा के अलावा उनके बेटे को ईडी का समन आया था या नहीं। आजकल ईडी का केस कहां चला गया है। नारायण राणे जब कांग्रेस में थे, तो उन पर जांच एजेंसियों की रेड हुई। ईडी और इनकम टैक्स के मुकदमे दर्ज हुए। नारायण राणे के भाजपा में शामिल होते ही वे पाक साफ बन गए। उनके खिलाफ ईडी व सीबीआई के केस अब कहां पर हैं।

कांग्रेस नेता अजय माकन ने सोमेन मित्रा का उदाहरण दिया है। सोमेन मित्रा, कांग्रेस और टीएमसी में भी रहे हैं। उन पर मुकदमा हुआ था। ईडी के सामने उनकी कई पेशी लगी थी। अब वे भाजपा में शामिल हो गए, तो सब कुछ खत्म हो गया।

सोमेन मित्रा और रमन सिंह का क्या हुआ

कांग्रेस नेता अजय माकन ने सोमेन मित्रा का उदाहरण दिया है। सोमेन मित्रा, कांग्रेस और टीएमसी में भी रहे हैं। उन पर मुकदमा हुआ था। ईडी के सामने उनकी कई पेशी लगी थी। अब वे भाजपा में शामिल हो गए, तो सब कुछ खत्म हो गया। रमन सिंह के ऊपर और उनके बेटे पर ईडी का केस है या नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के मुकदमे कहां चले गए हैं। कर्नाटक में जो मंत्री 40 फीसदी कमिशन खाते हुए पकड़े गए, उन पर ईडी के केसों का क्या हुआ। मुकुल रॉय, जब तक वे एक दूसरी पार्टी में थे, उन पर ईडी का केस था।

जैसे ही वे भाजपा में आए तो ईडी का केस ठीक हो गया। सुवेंदु अधिकारी, उन पर बहुत सारी कार्रवाई हुईं, लेकिन जैसे ही वे भाजपा में आए तो सब ठीक हो गया। ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। वह स्कीम चल रही है कि भाजपा में भर्ती हो जाओ और दूध से धुले बन जाओ।

ईडी क्या है?

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक सरकारी जांच एजेंसी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट यानि फेमा से जुड़े मामलों को देखती है। भारत में आर्थिक कानूनों का पालन करवाना और आर्थिक अपराधों से निबटने का काम ईडी के जिम्मे होता है। यह एजेंसी वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इतिहास 1 मई 1956 से चला आ रहा है। 1957 में इस यूनिट का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मुख्य रुप से एक जांच एजेंसी हैं। यह एजेंसी देश में विदेशी धन और निवेश में गड़बड़ी से जुड़े मामले देखती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मुख्यालय नई दिल्ली में जबकि इसके रीजनल ऑफिस मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ में है। इसके अलावा देश के दूसरे शहरों में भी ऑफिस हैं।

इनपुट – विभिन्न वेबसाइट एवं ईडी वेबसाइट

छापे में बरामद हुए करोड़ों रुपए और सोने के गहनों का आखिर होता क्या है?





ED हाई प्रोफाइल केसेज में अपनी छापेमारी को लेकर फिर सुर्खियों में हैं। ED एक हफ्ते के अंदर बंगाल की ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी से 50 करोड़ रुपए से अधिक कैश और 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद कर चुकी है।

ED की छापेमारी के बाद अर्पिता के घर से बरामद नोटों के ढेर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। नोटों के बंडलों को देखकर आपके मन में सवाल उठा होगा कि आखिर इतने पैसों का होगा क्या?

आईये जानते हैं कि आखिर ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियां, जो पैसे जब्त करती हैं, उसका क्या होता है?

ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स फ्रॉड या अन्य आपराधिक गतिविधियों में जांच, पूछताछ, छापेमारी करने और चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होता है।

ये एजेंसियां जब्त पैसे को अपनी कस्टडी में लेती हैं और फिर अदालत के आदेश से या तो उस पैसे को आरोपी को वापस कर दिया जाता है या फिर वो सरकार की संपत्ति बन जाता है।

ये पूरी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसमें कई चरण होते हैं...

इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता से बात की।

विराग ने कहा, ''केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे-ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी मामले की जांच के लिए छापा मारने का अधिकार होता है।

इन एजेंसियों को जांच करने का जो अधिकार होता है, उसके दो हिस्से होते हैं- एक गिरफ्तारी और पूछताछ और दूसरा उससे संबंधित सबूत इकट्ठा करने के लिए छापेमारी।''

''जांच एजेंसिया जो छापे मारती हैं वो अलग-अलग सूचनाओं पर आधारित होती हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि एक आरोपी के यहां एक ही बार छापा मारा जाए बल्कि छापेमारी कई चरणों में हो सकती है।"

ED को PMLA के तहत मिलता है संपत्ति जब्त करने का अधिकार

विराग गुप्ता का कहना है, ''अगर ED की बात करें तो उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी PMLA 2002 के तहत, अगर कस्टम डिपार्टमेंट है तो कस्टम एक्ट के तहत और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है।...

''जांच एजेंसी जिस कानून के तहत काम करती है, उसी के तहत उसे छापा मारने, जब्त करने और जब्त सामान को मालखाने या भंडारघर में जमा करने का अधिकार होता है।''

जब्त किए गए सामान का पंचनामा बनाती है ED

छापे में कई चीजें बरामद हो सकती हैं- इनमें पेपर डॉक्युमेंट्स, कैश और अन्य कीमती सामान जैसे सोने-चांदी के गहने मिल सकते हैं।

विराग ने बताया कि छापेमारी में जब्त की गई चीजों का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा जांच एजेंसी का IO यानी जांच अधिकारी बनाता है। पंचनामे पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। साथ ही इस पर जिस व्यक्ति का सामान जब्त होता है, उसके भी हस्ताक्षर होते हैं। पंचनामा बनने के बाद जब्ती का सामान केस प्रॉपर्टी बन जाता है।

27-28 जुलाई को चली 13 घंटे की रेड में ED ने ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया स्थित फ्लैट से 27.9 करोड़ कैश और 5 किलोग्राम सोना बरामद किया। इससे पहले 23 जुलाई को अर्पिता के टॉलीगंज स्थित फ्लैट में हुई छापेमारी में ED ने 21.9 करोड़ कैश, गहने और 76 लाख रुपए कीमत की विदेशी मुद्रा बरामद की थी।

27-28 जुलाई को चली 13 घंटे की रेड में ED ने ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया स्थित फ्लैट से 27.9 करोड़ कैश और 5 किलोग्राम सोना बरामद किया। इससे पहले 23 जुलाई को अर्पिता

के टॉलीगंज स्थित फ्लैट में हुई छापेमारी में एऊ ने 21.9 करोड़ कैश, गहने और 76 लाख रुपए कीमत की विदेशी मुद्रा बरामद की थी।

अब एक-एक करके जानते हैं ED जो कैश, गहने और संपत्ति जब्त करती है, उसका क्या होता है?

कैश

सबसे पहले जब्त किए गए पैसे या कैश का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए, कितनी गड्डियां हैं, कितने 200,500 और अन्य नोट हैं।

जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हों या कुछ लिखा हो या लिफाफे में हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती है, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके।

विराग कहते हैं कि बाकी पैसों को बैंकों में जमा कर दिया जाता है। जांच एजेंसिया जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती हैं।

कई बार कुछ पैसों को रखने की जरूरत होती है, तो उसे जांच एजेंसी इंटरनल ऑर्डर से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास जमा रखती है।

प्रॉपर्टी

ED के पास PMLA के सेक्शन 5 (1) के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को PMLA के सेक्शन 9 के तहत सरकार कब्जे में ले लेती है

विराग के अनुसार, ''जब ED किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करती है, तो उस पर बोर्ड लगा दिया जाता है, जिस पर लिखा होता है इस संपत्ति की खरीद-बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है।''

हालांकि कई मामलों में घर और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को अटैच किए जाने पर उनके इस्तेमाल को लेकर छूट भी है।

ED 180 दिनों के लिए अटैच कर सकती है प्रॉपर्टी

PMLA के तहत एऊ अधिकतम 180 दिन यानी 6 महीने के लिए किसी संपत्ति को अटैच कर सकती है।

अगर तब तक ED संपत्ति अटैच करने को अदालत में वैध नहीं ठहरा पाती है तो 180 दिन बाद संपत्ति खुद ही रिलीज हो जाएगी, यानी वो अटैच नहीं रह जाएगी।

अगर ED 180 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी अटैच करने को अदालत में सही साबित कर देती है तो संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। इसके बाद आरोपी को ED की इस कार्रवाई के खिलाफ ऊपर की अदालतों में अपील करने के लिए 45 दिन का समय मिलता है।

कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच होने के बावजूद काम करना रख सकती है जारी

ED के किसी संपत्ति को तात्कालिक जब्ती या प्रोविजनल अटैचमेंट करने से वह सील नहीं हो जाती है।

कई बार ऐसा भी होता है कि ED जिस संपत्ति को अटैच करती है, उस मामले की अदालत में सुनवाई जारी रहने के दौरान आरोपी उस संपत्ति का उपयोग कर सकता है।

उदाहरण के लिए 2018 में ED ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के दिल्ली स्थित जोरबाग के बंगले का 50% हिस्सा अटैच कर दिया था, लेकिन उस प्रॉपर्टी को खाली करने का कोर्ट का नोटिस मिलने तक उनका परिवार वहीं रह रहा था। चिदंबरम के बेटे कार्ति ने इस नोटिस के खिलाफ भी कानूनी राहत ले ली थी।

कॉमर्शियल प्रतिष्ठान ED के प्रॉपर्टी अटैच किए जाने के बाद भी बंद नहीं होते हैं। जैसे-दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल जैसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को भले ही ED ने अटैच कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद अदालत का फैसला आने तक वह काम करना जारी रख सकते हैं।

2018 में ED ने एअर इंडिया से जुड़े केस में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर स्थित क्लल्ल्ल होटल को अटैच कर दिया था, लेकिन होटल ने फिर भी बुकिंग करना जारी रखा था।

गहने

जांच एजेंसी अगर सोना-चांदी, गहने और अन्य कीमती सामान बरामद करती हैं, तो उसका भी पंचनामा बनता है।

पंचनामे में इस बात की पूरी जानकारी होती है कि-उसे कितना सोना या कितने गहने या कितना कीमती सामान बरामद हुआ।

विराग बताते हैं कि सोने-चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान को जब्त करके सरकारी मालखाने या भंडारघर में जमा कराया जाता है।

संपत्ति किसकी होगी, अदालत करती है आखिरी फैसला

कैश हो या गहने या प्रॉपर्टी, जब्त किए गए सामान पर आखिरी फैसला कोर्ट करती है। मुकदमा शुरू होने पर जब्त किए गए सामान को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है।

विराग का कहना है कि अगर अदालत जब्ती का आदेश देती है तो पूरी संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। अगर एऊ कोर्ट में जब्ती की कार्रवाई को सही नहीं साबित कर पाती तो संपत्ति संबंधित व्यक्ति को लौटा दी जाती है।

जब्ती को अदालत में चुनौती दिए जाने पर या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर अपीलकर्ता जब्त किए गए सामान को लीगल साबित कर देता है तो उसे जब्त किया गया सारा सामान वापस मिल जाता है।

कई बार कोर्ट जिसकी संपत्ति है, उस पर कुछ फाइन लगाकर भी उसे संपत्ति लौटाने का मौका देती है।

विराग ने बताया कि जांच एजेंसियां प्रशासनिक आदेश से ही संपत्ति को अटैच करती हैं और फिर कोर्ट के ऑर्डर से वो सरकार की हो जाती है या जिसकी संपत्ति जब्त की गई है, उसे लौटा दी जाती है।



चीन को 2030 तक पीछे छोड़ देगा भारत, तेजी से बढ़ रही है भारत की आबादी

भारत में आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसमें मुस्लिम और दलितों की आबादी का आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट की मानें तो साल 2030 तक भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। क्या है आबादी बढ़ने के कारण? क्या वाकई मुस्लिम आबादी बढ़ रही है? क्या कहते हैं आंकड़े पढ़िये।

- रवीन्द्र कुमार

यूनाइटेड नेशन्स ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं, बढ़ती जनसंख्या पर वढ के उट योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों से कहा है कि जनसंख्या कंट्रोल के प्रयास सफलता पूर्वक किए जाएं, ताकि ऐसा न हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने से समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाए।

देश में पिछले चार दशक से भी ज्यादा समय में बढ़ती जनसंख्या को एक गंभीर समस्या के रूप में देखा जा रहा है। 70 के दशक में जनसंख्या रोकने के लिए भारत की सरकार ने कई कदम उठाये। सरकार के द्वारा उठाये गए कई कदमों पर उस समय कई तरह के आरोप भी लगे। उस दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने नसबंदी का एक कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के तहत नसबंदी करवाने वाले व्यक्ति को इनाम भी दिया जाता था लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर यह बात सामने आयी की कुछ अस्पतालों के द्वारा अपने टारगेट पूरा करने के चक्कर में डॉक्टरों ने ऐसे लोगों की नसबंदी कर दी जिनकी शादी तक नहीं हुई थी।

चलिए, ये तो उस दौर की बात थी। जिस समय बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण के लिए हम दो हमारे तीन का नारा दिया गया। इसके बाद हम दो हमारे दो और इसके बाद हम दो हमारा एक का भी नारा दिया गया। लेकिन भारत की जनसंख्या इन नारों से नहीं रूकी। हालांकि कुछ लोगों में जागृति आयी जरूर लेकिन आगे चलकर कुछ धार्मिक रीति रिवाज तो कुछ धार्मिक कट्टरता के चलते जनसंख्या नियंत्रण भारत में अभी तक फेल यानी असफल ही माना जाता रहा है।

यह कहना इसलिए भी गलत नहीं है कि आजादी के बाद यानी साल 1947 में भारत की आबादी 43 करोड़ के आसपास थी। जो आज बढ़कर एक सौ 36 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। सोचने और कहने में यह अजीब लगे लेकिन सच यह है कि भारत के लोगों ने जितना ध्यान आबादी बढ़ाने और बच्चे पैदा करने पर दिया है। अगर उतना ध्यान, देश के विकास पर लगाते तो शायद आज हम दुनिया के विकसित देशों में शामिल होते।

लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बढ़ती आबादी के कारण भारत में कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा ने न सिर्फ अपने पैर पसारे बल्कि देश को भी पीछे छोड़ दिया।

वहीं, अब एक नयी बहस भी आबादी को लेकर बढ़ रही है। भारत में खासतौर पर इस बात को हवा दी जा रही है कि भारत की आबादी मुस्लिम समुदाय की वजह से ज्यादा बढ़ी है। यह बात एक नजर में सही तो लगती है लेकिन इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है जितनी बताई जाती है।

असल में 2030 तक 24 करोड़ हो सकती है मुस्लिमों की आबादी

यूनाइटेड नेशन्स ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं, बढ़ती जनसंख्या पर वढ के उट योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों से कहा है कि जनसंख्या कंट्रोल के प्रयास सफलता पूर्वक किए जाएं, ताकि ऐसा न हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने से समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाए।

ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि क्या क्या वाकई सिर्फ किसी एक समुदाय की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, आजादी के बाद किस धर्म से जुड़े लोगों की कितनी आबादी थी और अब कितनी है, आबादी बढ़ने के मामले में क्या धार्मिक वजह जिम्मेदार हैं।

2023 में भारत बनेगा दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश: UN

'वर्ल्ड पॉपुलेशन डे' के मौके पर पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है...

चीन की आबादी: 142.6 करोड़ है।

भारत की आबादी: 141.2 करोड़ है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा।

2050 में..

भारत की संभावित आबादी: 166 करोड़ है।

चीन की संभावित आबादी: 131 करोड़ है।

प्यू रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2021 में मुस्लिमों की भारत में आबादी 21.30 करोड़ थी, जो 2030 तक 23.63 करोड़ हो जाएगी। यानी इन 8 सालों के दौरान मुस्लिमों की पापुलेशन ग्रोथ करीब

10% रहेगी। वहीं भारत की आबादी इस समय बढ़कर 150 करोड़ तक होने का अनुमान है।

आजादी के बाद 73 सालों में कितनी बढ़ी देश की आबादी?

स्टेटिस्टा के मुताबिक 1948 में देश की आबादी 35.8 करोड़ थी। 2020 में देश की आबादी बढ़कर करीब 138 करोड़ हो गई है। इस तरह देखा जाए तो 72 साल में देश की आबादी 103 करोड़ बढ़ी है।

देश भर में सरकारी संस्थाओं द्वारा आबादी की गिनती 2011 में आखिरी बार हुई है। इसलिए इसे अंतिम सेंसस कहते हैं। अब इसी सेंसस के आधार पर किस धर्म में कितनी आबादी बढ़ी या घटी है, उसे कुछ इस तरह से समझते हैं।

10 साल में मुस्लिमों की आबादी 24.78% और हिंदुओं की 16.77% बढ़ी

2001 में हिंदुओं की आबादी 82.75 करोड़ और मुस्लिम आबादी 13.8 करोड़ थी। ठीक 10 साल बाद हिंदुओं की आबादी बढ़कर 96.63 करोड़, जबकि मुस्लिमों की आबादी 17.22 करोड़ हो गई। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी 24.78% की रफ्तार से जबकि हिंदुओं की 16.77% की रफ्तार से बढ़ी है।

इस तरह भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी 2001 में 13.4% थी जो 10 साल बाद बढ़कर 14.2% हो गई। वहीं, इस एक दशक में हिंदुओं कुल जनसंख्या में आबादी 80.45% से घटकर 79.8% हो गई।

यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि भारतीय मुसलमानों में 80% आबादी पसमांदा मुसलमानों की है। पसमांदा मतलब जो पिछड़ा हुआ है। यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे।

इसी नजर ऊपर दिए आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाता है कि तेजी से आबादी का बढ़ना सीधे-सीधे धर्म से जुड़ा नहीं बल्कि इसका सामाजिक आर्थिक हालात ज्यादा लेना-देना है।

इस तर्क को आदिवासियों के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। साल 1951 से 2011 के बीच आदिवासियों की जनसंख्या भी तेज रफ्तार से 5.6% से बढ़कर 8.6% हो गई।

'प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सुविधा से है।'

आलोक बाजपेयी, जॉइंट डायरेक्टर, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया

अब तक आपने पढ़ा कि जनसंख्या कैसे बढ़ी, लेकिन अब देखिए कैसे 1990 के बाद जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है...

2015 में मुस्लिमों में प्रजनन दर 2.6 और हिंदुओं में 2.1 थी

भारत में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2015 में हर मुसलमान महिला के औसतन 2.6 बच्चे थे। वहीं, हिंदू महिलाओं के बच्चों की संख्या औसतन 2.1 थी। सबसे कम फर्टिलिटी रेट जैन समूह की पाई गई। जैन महिलाओं के बच्चों की औसत संख्या 1.2 थी।

रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा 4.4 थी। दूसरे नंबर पर हिंदू 3.3 थे। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार जनसंख्या दर में कमी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में आई है, जो 1990 के पहले तक हिंदुओं से कहीं ज्यादा हुआ करती थी।

एक हकीकत ये भी है.....

जम्मू-कश्मीर, केरल, प. बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, वहां भी फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत 1.8 से नीचे है। इसमें वढ अपवाद है, जहां, दर 2.4 है। इसके अलावा देश में सर्वाधिक 3 फर्टिलिटी रेट बिहार में है। वहीं, मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4, झारखंड में 2.3 और राजस्थान में 2.1 है।

दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार

हमने दुनिया के बाकी देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार को जानने के लिए वर्ल्ड बैंक के डेटा से एनालिसिस किया। इसमें पता चला कि सऊदी अरब में 33.49% की रफ्तार से जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच बढ़ी है। वहीं, नाइजीरिया में 29.82% और पाकिस्तान में 25.54% की दर से जनसंख्या एक दशक में बढ़ी है। इसके अलावा भारत में मुस्लिमों की आबादी इस एक दशक में 24.78% की रफ्तार से बढ़ी है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की आबादी के पीछे सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और धार्मिक मान्यता है। वह किसी भी धर्म के साथ हो सकती हैं।

वहीं सच यह भी है कि अगर भारत की आबादी ठीक इसी तरह से बढ़ती चली गयी तो वह दिन दूर नहीं जब भारत में एक तरफ खाने पीने की समस्या होगी वहीं दूसरी ओर आम लोगों के स्वास्थ्य, घर और सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा।

बेरोजगारी और अशिक्षा बढ़ेगी साथ ही देश के विकास का पहिया भी रूक जाएगा। इसलिए सभी चीजों को दरकिनार कर यह समझना आवश्यक है कि मौजूदा दौर में बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए चुनौती है। और इसे हर हाल में हम मनुष्यों को ही रोकना होगा। और कहा भी जाता है कि बगैर बुलाएं बाराती खाली पेट ही घर जाते हैं। ऐसा न हो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है।

आबकारी नीति विवाद पर अनिल बैजल ने तोड़ी चुप्पी, सिसोदिया के आरोपों पर बोले- समय और जांच से सामने आएगा सच

मनीष सिसोदिया द्वारा निजी कंपनियों का पक्ष लेने के आरोपों पर पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के सभी गैरकानूनी फैसलों पर सवाल उठाए थे। बकारी नीति विवाद पर अनिल बैजल ने तोड़ी चुप्पी, सिसोदिया के आरोपों पर बोले- समय और जांच से सामने आएगा सच

-ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो



दिल्ली आबकारी नीति विवाद के बीच पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उन पर लगे आरोपों पर आज चुप्पी तोड़ी है। बैजल ने मंगलवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को 'निराधार और प्रेरित' बताते हुए खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार द्वारा संबंधित आबकारी नीति लाए जाने के समय बैजल उपराज्यपाल थे।

आबकारी विभाग का भी दायित्व संभाल रहे मनीष सिसोदिया ने पिछले शनिवार को अनिल बैजल पर आबकारी नीति पर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया था। सिसोदिया कहा था कि बैजल के फैसले से कुछ लाइसेंसधारियों को लाभ हुआ, जबकि दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

बैजल ने आज अपने बेहद कड़े बयान में कहा कि सिसोदिया द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप 'अपनी खाल बचाने के लिए हताश आदमी' द्वारा किया जा रहा प्रयास है।

सिसोदिया द्वारा निजी कंपनियों का पक्ष लेने के आरोपों पर पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के सभी गैरकानूनी फैसलों पर सवाल उठाए थे। बैजल ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कहा कि सिसोदिया अपने और अपने सहयोगियों के कृत्यों तथा गलतियों के लिए कुछ बहाना खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप कुछ और नहीं, बल्कि एक हताश आदमी द्वारा अपनी खाल बचाने के लिए कहा जा रहा प्रयास है। बैजल ने 'आप' सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि समय और जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।

पूर्व उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने कई मौकों पर 'आप' सरकार द्वारा लिए गए 'गैरकानूनी फैसलों' को हरी झंडी दिखाई थी, जिन्हें फाइलों में संशोधित किया जाना था। उन्होंने कहा कि नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकानों की अनुमति नहीं देने के मामले में मैंने देश के कानून को बनाए रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज भी कोई कानून नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं देता है।

बैजल ने दिल्ली सरकार और सिसोदिया के दावों को खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड खुद बोलेंगे। उन्होंने कहा कि जांच के बाद सच सामने आएगा।

वर्क फॉर्म होम से बढ़ रही है टाइप टू डायबिटीज की समस्या

-ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो

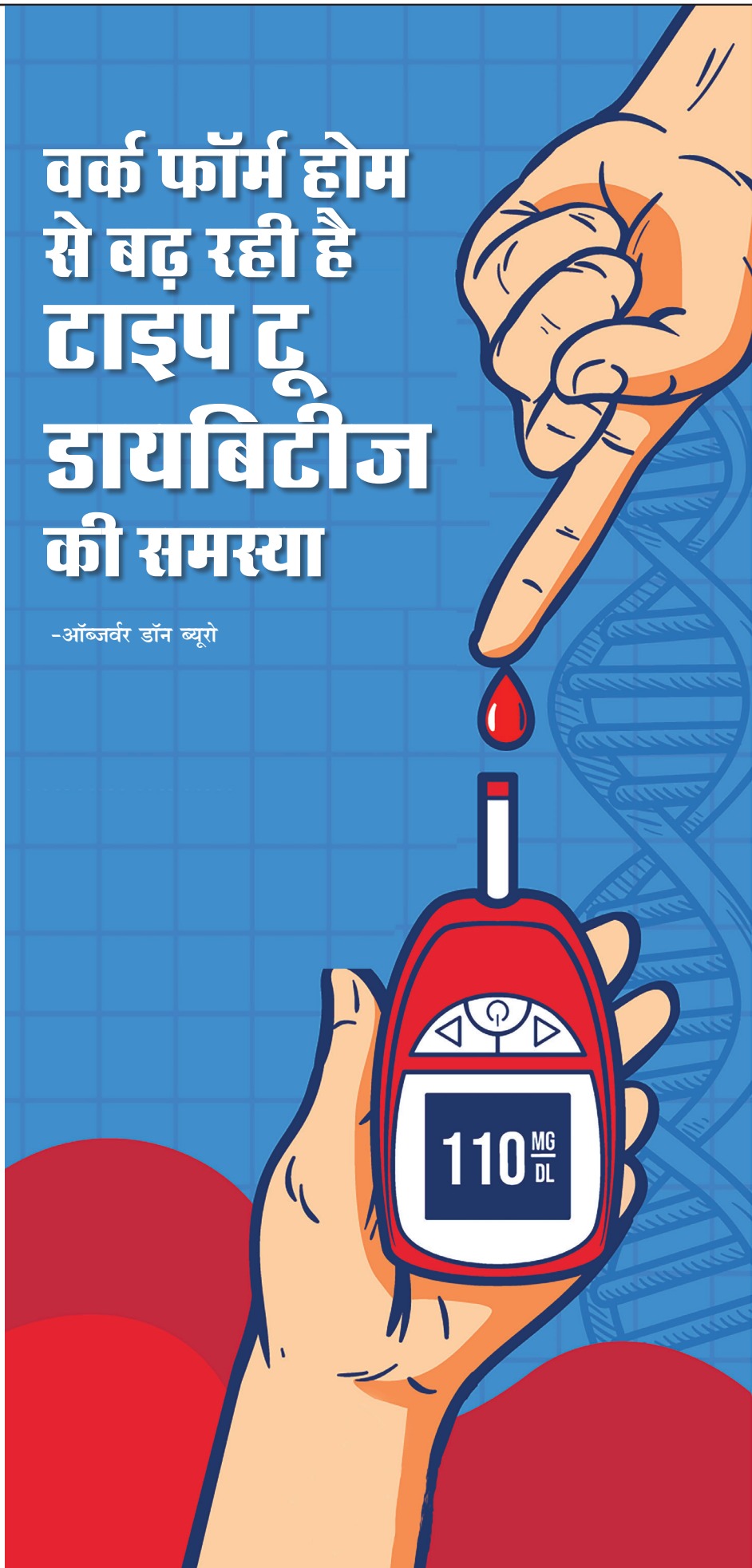

आज के तेज भागदौड़ के दौर में शुगर एक आम समस्या होती जा रही है। ऑफिस दफ्तर और घर में घंटों बैठकर दफ्तर का काम करना अब जान पर भारी पड़ता जा रहा है।

हालांकि शुगर की समस्या से पहले भी भारत और दुनिया के लोग जूझ रहे थे, लेकिन अब शुगर की समस्या एक नये रूप में हमारे सामने है।

एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि अगर समय रहते शुगर पर नियंत्रण नहीं पाया जाए तो यह जानलेना साबित हो सकती है।

कितने प्रकार की होती है डायबिटीज

वंशानुगत कारणों से होनेवाली डायबिटीज को टाइप-1 डायबिटीज कहा जाता है। जबकि कुछ लोगों में गलत लाइफस्टाइल के कारण यह बीमारी घर कर जाती है। इस स्थिति को टाइप-2 डायबिटीज कहते हैं।

डायबिटीज एक और दो के फर्क को कैसे समझे

डायबिटीज टाइप-1 और डायबिटीज टाइप-2 सुनकर अक्सर लोगों के जेहन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये डायबिटीज एक और डायबिटीज दो है क्या? दोनों ही डायबिटीज के बीच अंतर क्या है? क्या इनके लक्षण अलग-अलग होते हैं यह एक जैसे ही होते हैं?

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि डायबिटीज की बीमारी क्यों होती है और कौन इससे ग्रस्त हो सकते हैं?

मौजूदा दौर में ज्यादातर लोगों की जीवनशैली बेहद खराब हो चली है। पार्क में घूमना फिरना या फिर व्यायाम करना जैसे हम भूलते ही जा रहे हैं। थोड़ा बहुत योगा और पार्क में टहल कर हमे लगता है कि बस हो गया। वहीं, खान पान की गलत आदतें, जिसमें तला भूना, ज्यादा मसालेदार और फास्ट फूड खाने की लत ने हमारे

शरीर को अंदर से खोखला कर दिया है। एक तरफ यह हमारे अमाश्य को कमजोर बने रहे हैं तो दूसरी ओर जीभ का स्वाद बढ़ाकर हमारे पाचन तंत्र की धज्जियां उड़ा रहे है।

धीरे धीरे जब हमारे शरीर में पैक्रियाज (अग्नाश्य) इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कम कर देता है या बंद कर देता है तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। अगर इस स्तर को कंट्रोल ना किया जाए तो हम शुगर के रोगी बन जाते हैं।

दो तरह की होती है शुगर की बीमारी

- शुगर की बीमारी दो तरह की होती है। टाइप-1 और टाइप-2, इनमें टाइप-1 शुगर वह है जो हमें अनुवांशिक तौर पर होती है। यानी जब किसी के परिवार में मम्मी-पापा, दादी-दादा में से किसी को शुगर की बीमारी रही हो तो ऐसे व्यक्ति में इस बीमारी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।
- यदि किसी व्यक्ति को वंशानुगत कारणों से डायबिटीज होती है तो इसे टाइप-1 डायबिटीज कहा जाता है। जबकि कुछ लोगों में गलत लाइफस्टाइल और खान-पान के कारण यह बीमारी घर कर जाती है। इस स्थिति को टाइप-2 डायबिटीज कहते हैं।

क्यों होती है डायबिटीज, क्या हैं इसके प्रारंभिक लक्षण? जानें हर सवाल का जवाब

जन्म से भी हो सकती है ऐसी डायबिटीज

- डायबिटीज टाइप-1की समस्या किसी बच्चे में जन्म से भी देखने को मिल सकती है। या बहुत कम उम्र में भी यह बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। इस स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है।
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वंशानुगत कारणों से पैंक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। यानी इसमें अपने ही शरीर की कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं के दुश्मन की तरह रिऐक्ट करती हैं और उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती हैं।
- डायबिटीज टाइप-1 में हमारे ही शरीर की कुछ कोशिकाएं हमारे पैक्रियाज यानी अग्नाश्य की कोशिकाओं पर हमला करके इंसुलिन के उत्पादन को बाधित कर देती हैं। इससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है।

sugur-2

डायबिटीज टाइप-1 और डायबिटीज टाइप-2 में अंतर

डायबिटीज-2 इन कारणों से भी होती है

- डायबिटीज टाइप-2 बहुत अधिक फैट, हाई बीपी, समय पर ना सोना, सुबह देर तक सोना, बहुत अधिक नशा करना और निष्क्रिय जीवनशैली के कारण भी होती है।
- डायबिटीज टाइप-2 का एक कारण शरीर में इंसुलिन कम बनना भी होता है। ऐसा कुछ शारीरिक कारणों या गलत खान-पान के कारण भी हो सकता है।
- इंसुलिन कम बनने से रक्त में मौजूद कोशिकाएं इस हॉर्मोन के प्रति बहुत कम संवेदनशीलता दिखाती हैं। इस कारण भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति डायबिटीज टाइप-2 का शिकार हो जाता है।

शुगर इस तरह करती है परेशान

- जब हमारा अग्नाश्य इंसुलिन नाम का हॉर्मोन बनाता है तो शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड में फ्लो नहीं करता। बल्कि ऊर्जा के रूप में शरीर में स्टोर हो जाता है। इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तब हम कहते हैं फैट बढ़ रहा है।
- जब हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है और हम कुछ खा नहीं पाते हैं तब हमारा शरीर इस स्टोर फैट का उपयोग करता है। ताकि सभी अंग ठीक से काम करते रहें।
- लेकिन इंसुलिन के अभाव में शुगर कोशिकाओं में स्टोर ना होकर ब्लड में ही घूमती रहती है। इससे रक्त में मौजूद रेड ब्लड सेल और वाइड ब्लड सेल अपना काम नहीं कर पाती हैं। जिससे हमें जल्दी-जल्दी बीमारियां होने लगती हैं और मामूली बीमारी को ठीक होने में भी लंबा वक्त लग जाता है।

#diabetes-2

शुगर की बीमारी और इलाज का तरीका

ट्रीटमेंट से जुड़ी बातें

- किसी भी मरीज को यदि केवल शुगर की समस्या है तो उसके इलाज में उन लोगों के इलाज से अंतर होता है, जिन्हें शुगर या डायबिटीज के साथ ही दूसरी बीमारियां भी हों।
- डायबिटीज टाइप-1 का इलाज करते समय पेशंट को समय-समय पर इंसुलिन देना होता है। क्योंकि इस स्थिति में शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है।
- डायबिटीज टाइप-1 की बीमारी वंशानुगत होती है, इसलिए इस पर जीवनशैली में बदलावों के साथ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है।
- वहीं, डायबिटीज टाइप-2 में जरूरत होने पर ही इंसुलिन की डोज दी जाती है। नहीं तो ऐसी दवाओं से चिकित्सा की जाती है, जो इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पैंक्रियाज को प्रोत्साहित करें।
- इसके साथ ही सही जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया जाता है। तनाव को कम करने के लिए शारीरिक गतिविधियों और ध्यान की सहायता ली जाती है।

आयुर्वेद में क्या इसका इलाज है?

जी हां, आयुर्वेद में शुगर का इलाज है, लेकिन यह इलाज तभी कारगर सिद्ध होता है जब आप इसे सही तरीके से अपनाये। यह इलाज टाइप टू शुगर में कारगर सिद्ध होता है। इसमें व्यायाम के साथ आयुर्वेद की दवाएं दी जाती है।

गंदा पानी पीने से हो सकता है कैंसर और अल्जाइमर, देश की 80% से ज्यादा आबादी जहरीला पानी पी रही है।

-ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो



घर में पानी नहीं, जहर पी रहे हैं आप

सरकार ने खुद दिखाए आंकड़े

सही पढ़ा आपने। जल शक्ति मंत्रालय के एक डॉक्युमेंट के अनुसार, देश की 80% से ज्यादा आबादी के घरों में पानी ग्राउंड वाटर से जाता है। जिसमें जहरीली धातुओं की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है। मतलब साफ है कि पानी जहर बनता जा रहा है।

सरकार के मुताबिक 209 जिलों के ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और 491 जिलों में आयरन की मात्रा तय मानक से ज्यादा मिली है। जो चिंताजनक है।

पीने के पानी में आर्सेनिक या आयरन की मात्रा ज्यादा होने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी मात्रा ज्यादा है और इससे बचने के उपाय क्या हैं... सब कुछ आज जरूरत की खबर में जानेंगे।

सवाल- आर्सेनिक और आयरन होता क्या है, जिसकी मात्रा पानी में बढ़ने से वो जहरीला माना जा रहा है?

जवाब- आर्सेनिक- ये एक केमिकल एलिमेंट है। यह वातावरण में नेचुरल तरीके से मौजूद होता है। कुछ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में घुल जाता है। फिर पानी के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है।

आयरन- आर्सेनिक की तरह आयरन भी एलिमेंट है। मानव शरीर के न्यूट्रिशन में आयरन एक जरूरी एलिमेंट है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको हर रोज तय मानक के हिसाब से आयरन को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।

सवाल- आर्सेनिक और आयरन शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं?

जवाब- डॉ. वी पी पांडे के मुताबिक, हमारा शरीर को बहुत कम मात्रा में आर्सेनिक चाहिए होता है, जो आसानी से बाहर (पेशाब के जरिए) निकल जाता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो ये शरीर में कई तरह के निगेटिव इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। वहीं आयरन हमारे शरीर में खून बनाने के लिए जरूरी फैक्टर है। इसके न होने से खून की कमी हो जाती है, लेकिन शरीर में तय मात्रा में ही आयरन का होना जरूरी है। जब लंबे समय तक ज्यादा आयरन शरीर में जाता है, तो यह जहर की तरह काम करने लगता है। इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं।

आर्सेनिक और आयरन के अलावा कुछ और चीजें भी

ग्राउंड वाटर में ज्यादा पाई गई हैं। एक नजर उन पर भी डाल लीजिए-

11 राज्यों के 29 जिलों के ग्राउंड वाटर में कैडमियम की मात्रा 0.003 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है।

16 राज्यों के 62 जिलों के ग्राउंड वाटर में क्रोमियम की मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा देखी गई है।

18 राज्यों में 152 जिले के ग्राउंड वाटर में 0.03 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा यूरेनियम मिला है।

आंकड़ों के बाद जानते हैं कि जब पानी में इन सभी चीजों की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। पानी में कैडमियम ज्यादा होने से किडनी, लिवर, हड्डी और ब्लड रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं।

पानी में क्रोमियम की मात्रा ज्यादा होने से छोटी आंत में हाइपरलेशिया डिफ्यूज और ट्यूमर का खतरा बढ़ सकता है।

पानी में यूरेनियम की ज्यादा होने पर किडनी से रिलेटेड बीमारियां और कैंसर होने की आशंका रहती है।

(सोर्स- University of California, Water Quality Association)

शहर से ज्यादा गांव की हालत खराब

देश की आधे से ज्यादा आबादी गांवों में रहती हैं। यहां पीने के पानी का मुख्य जरिया ही ग्राउंड वाटर है। जैसे- हैंडपंप, कुआं, नदी-तालाब या बोरवेल।

सवाल उठता है कि शहर हो या गांव, जिन लोगों के घरों में ग्राउंड वाटर आता है या कुआं, हैंडपंप नदी-तालाब या बोरवेल से डायरेक्ट पानी आता है, उन्हें कैसे पता लगेगा कि उनके पानी में आयरन और आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है या नहीं? इसके लिए नीचे दिए ग्राफिक्स को पढ़ें और दूसरों के साथ शेयर भी करें...

सवाल- पीने के पानी में आयरन और आर्सेनिक कितना होना चाहिए?

जवाब- क्लटफ ने पीने के पानी में ज्यादा से ज्यादा आयरन की मात्रा 1.0 ढढइ तय की है।

आर्सेनिक के लिए निर्देशित मानक या मैक्सिमम कंटामिनेशन लेवल (टछउ) 10 ढढइ (हलृड के अनुसार) है, जिसे ज्यादातर विकसित देश मानते हैं। विकासशील देश जिनमें भारत और बांग्लादेश भी शामिल हैं,व हां पीने वाले पानी में आर्सेनिक की मात्रा 50 ढढइ मानी गई है।

सवाल- अगर वाटर टेस्टिंग की रिपोर्ट में आपके घर का पानी पीने लायक नहीं बताया जाता है तो क्या होता है?

जवाब- अगर आपके घर के पानी में कोई भी मिनरल ज्यादा होता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो उस कुएं, हैंडपंप या बोरवेल को बंद कर दिया जाता है। फिर घर पर किसी और रिसोर्स के जरिए पानी लेने के सलाह दी जाती है। जैसे- नगरपालिका के नल का कनेक्शन लें।

सवाल- कई बार आंधी-तूफान या बाढ़ जैसी इमरजेंसी अचानक आ जाती है। ऐसे में हो सकता है कि हमारे नल में पानी न आए और कुएं, हैंडपंप या बोरवेल का पानी पीने लायक न हो। ऐसी सिचुएशन में बीमारी से बचने के लिए हम कैसे पानी पिएं।

जवाब- उञ्ज के अनुसार, जब तक आपके घर में पीने लायक पानी का सप्लाई न हो तब तकङ्ख

खाना पकाने, पर्सनल हाइजीन और पीने के लिए बोतल बंद, उबला हुआ या किसी दूसरे घर से पानी मांगकर इस्तेमाल करें। पानी को उबालने और ट्रीट करने के लिए अपने एरिया के स्टेट, लोकल और ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट की सिफारिशों को फॉलो करें।

जिस पानी में फ्यूल, रेडियोएक्टिव मटेरियल, केमिकल या कोई मिनरल ज्यादा है, उसे उबालने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए पानी का दूसरा सोर्स मिलने तक बोतलबंद या किसी दूसरी जगह से लेकर ही पानी पिएं।

अपने घर के अंदर और बाहर पानी सप्लाई के दूसरे सोर्स को तलाशें, जहां से पीने लायक पानी मिल सके। कभी भी रेडिएटर या बॉयलर से पानी गर्म न करें।

सवाल- आजकल शहरों में बहुत से लोग वाटर प्यूरीफायर लगवाते हैं। क्या ये पीने के पानी में आयरन और आर्सेनिक की मात्रा को कंट्रोल कर सकता है?

जवाब- वाटर प्यूरीफायर कई तरह के होते हैं। आपको खरीदने से पहले इस बात को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वाटर प्यूरीफायर आर्सेनिक और आयरन को कंट्रोल कर सकता है और कौन सा नहीं।

चलते-चलते

केंद्र ने जो आंकड़े राज्यसभा में पेश किए हैं, उस पर भी नजर डाल लीजिए-

रिहायशी इलाकों में भी पीने के पानी के स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की मानें तो 671 इलाके फ्लोराइड, 814 इलाके आर्सेनिक, 1,4079 इलाके आयरन, 9,930 इलाके खारापन, 517 इलाके नाइट्रेट और 111 इलाके भारी धातु से इफेक्टेड हैं।

जरूरी बात- किसी इंसान को हेल्दी रहने के लिए हर दिन कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। कोई भी इंसान बिना खाने के महीनेभर तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के सिर्फ एक हफ्ते तक ही। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में औसतन 75 हजार लीटर पानी पी जाता है।



RBI ने ब्याज दरें 0.50% बढ़ाईं:

लोन महंगे होंगे, 20 साल वाले 30 लाख के होम लोन की EMI करीब 900 रु. ज्यादा होगी

आप के घर की ईएमआई महंगी हो सकती है। जी हां, आरबीआई ने ब्याज की दरों में इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद ब्याज दरें अगस्त 2019 के लेवल पर पहुंच गई है। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 3 अगस्त से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरें बढ़ाने की जानकारी दी।

0.50% रेट बढ़ने से कितना फर्क पड़ेगा

मान लीजिए रोहित नाम के एक व्यक्ति ने 7.55% के रेट पर 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का हाउस लोन लिया है। उसकी लोन की EMI 24,260 रुपए है। 20 साल में उसे इस दर से 28,22,304 रुपए का ब्याज देना होगा। यानी, उसे 30 लाख के बदले कुल 58,22,304 रुपए चुकाने होंगे। अमित के लोन लेने के एक महीने बाद RBI रेपो रेट में 0.50% का इजाफा कर देता है। इस कारण बैंक भी 0.50% ब्याज दर बढ़ा देते हैं। अब जब अमित का एक दोस्त उसी बैंक में लोन लेने के लिए पहुंचता है तो बैंक उसे 7.55% की जगह 8.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है।

अमित का दोस्त भी 30 लाख रुपए का ही लोन 20 साल के लिए लेता है, लेकिन उसकी EMI 25,187 रुपए की

ब्याज दरों पर फैसले के लिए 3 अगस्त से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। फ्हक गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरें बढ़ाने की जानकारी दी।

बनती है। यानी अमित की EMI से 927 रुपए ज्यादा। इस वजह से अमित के दोस्त को 20 सालों में कुल 60,44,793 रुपए चुकाने होंगे। ये अमित की रकम से 2,22,489 ज्यादा है।

यहां दी गई ब्याज दरें सिर्फ अनुमान है। बैंक रेपो रेट बढ़ने या घटने पर अपने हिसाब से ब्याज दरें बढ़ाता या घटाता है।

यहां दी गई ब्याज दरें सिर्फ अनुमान है। बैंक रेपो रेट बढ़ने या घटने पर अपने हिसाब से ब्याज दरें बढ़ाता या घटाता है।

क्या पहले से चल रहे लोन पर भी बढ़ेगी एटक

होम लोन की ब्याज दरें 2 तरह से होती हैं पहली फ्लोटर और दूसरी फ्लेक्सिबल। फ्लोटर में आपके लोन कि ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक जैसी रहती है। इस पर रेपो रेट में बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं फ्लेक्सिबल ब्याज दर लेने पर रेपो रेट में बदलाव का आपके लोन की ब्याज दर पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में

होम लोन की ब्याज दरें 2 तरह से होती हैं पहली फ्लोटर और दूसरी फ्लेक्सिबल। फ्लोटर में आपके लोन कि ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक जैसी रहती है। इस पर रेपो रेट में बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ता।

अगर आपने पहले से फ्लेक्सिबल ब्याज दर पर लोन ले रखा है तो आपके लोन की EMI भी बढ़ जाएगी।

चार महीने में 1.40% की बढ़ोतरी

मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर दो महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। तब RBI ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था। लेकिन RBI ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। 22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में ये बदलाव हुआ था।

इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग 6-8 अप्रैल को हुई थी। इसके बाद 6 से 8 जून को हुई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट में 0.50% इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गई थी। अब अगस्त में इसे 0.50% बढ़ाया गया है जिससे ये 5.40% पर पहुंच गई है।



RBI गवर्नर ने क्या कहा?

- रेपो रेट में 0.50% बढ़ाने का फैसला
- FY23 रियल GDP ग्रोथ अनुमान 7.2% पर बरकरार
- सप्लाई बढ़ने से खाने के तेल की कीमतों में कमी
- FY23 में महंगाई दर 6.7% संभव
- करेंट अकाउंट डेफिसिट चिंता की बात नहीं
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर महंगाई का असर
- ग्लोबल स्तर पर महंगाई चिंता का विषय
- MSF 5.15% से बढ़ाकर 5.65% की
- MPC बैठक में अकोमोडेटिव रुख वापस लेने पर फोकस
- अप्रैल के मुकाबले महंगाई में कमी आई
- शहरी मांग में सुधार देखने को मिल रहा है
- बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में सालाना 14% की बढ़ोतरी
- बेहतर मानसून से ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी संभव



RBI रेपो रेट क्यों बढ़ाता या घटाता है?

RBI के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो, RBI रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को RBI से मिलेने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देंगे। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा। मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड में कमी आएगी और महंगाई घटेगी।

इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में RBI रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को RBI से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। इस उदाहरण से समझते है। कोरोना काल में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी तो डिमांड में कमी आई थी। ऐसे में RBI ने ब्याज दरों को कम करके इकोनॉमी में मनी फ्लो को बढ़ाया था।

बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 4.90% से बढ़कर 5.40% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा एटक चुकानी होगी।

रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने-घटने से क्या होता है?

रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते है जिस दर पर बैंकों को RBI पैसा रखने पर ब्याज देता है। जब RBI को मार्केट से लिक्विडिटी को कम करना होता है तो वो रिवर्स रेपो रेट में इजाफा करता है। फ्रिक के पास अपनी होल्डिंग के लिए ब्याज प्राप्त करके बैंक इसका फायदा उठाते हैं। इकोनॉमी में हाई इंफ्लेशन के दौरान RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है। इससे बैंकों के पास ग्राहकों को लोन देने के लिए फंड कम हो जाता है।

प्राइस राइज टॉलरेंस लेवल से बहुत आगे

जून की पॉलिसी के दौरान, फ्रिक गवर्नर ने कहा था कि प्राइस राइज टॉलरेंस लेवल से बहुत आगे है। हालांकि, उन्होंने हाल

ही में अपने एक बयान में कहा था कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में महंगाई कम होगी। दास ने कहा था, मौजूदा समय में सप्लाई का आउटलुक काफी बेहतर नजर आ रहा है। सभी इंडिकेटर्स 2022-23 की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था की रिकवरी के संकेत दे रहे हैं।

जानिए महंगाई के आंकड़े क्या कहते हैं?

1. जून में भारत की रिटेल महंगाई 7.01%

पिछले महीने की शुरूआत में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून में भारत की रिटेल महंगाई 7.01% हो गई। एक साल पहले की समान अवधि में ये 6.26% थी। यह लगातार छठा महीना था जब महंगाई केंद्रीय बैंक के 2%-6% के टॉलरेंस बैंड से ऊपर रही थी।

2. खाद्य महंगाई दर 7.75% रही थी

खाद्य महंगाई दर जून में 7.75% रही जो मई में 7.97% रही थी। अप्रैल में यह 8.38% थी। सब्जियों की महंगाई जून में घटकर 17.37% हो गई जो मई में 18.26% थी। फ्यूल और लाइट की महंगाई जून में बढ़कर 10.39% हो गई जो मई में 9.54% थी।

महंगाई कैसे प्रभावित करती है?

महंगाई का सीधा संबंध पर्चेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए, यदि महंगाई दर 7% है, तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 93 रुपए होगा। इसलिए, महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी।

अमेरिका में ब्याज दरों में 0.75% का इजाफा

अमेरिकी केंद्रीय बैंक वर फेडरल रिजर्व ने हाल ही में ब्याज दरों में 0.75% का इजाफा किया था। वर फेड ने महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार दूसरी बार अपनी पॉलिसी को सख्त करते हुए ब्याज दरों में इजाफा किया था। अमेरिका में अब ब्याज दरें बढ़कर 2.50% तक हो गई हैं। इससे पहले, जून 2022 में भी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% का इजाफा किया था।

महंगाई दर 1980 के बाद से सबसे ज्यादा

अमेरिका में महंगाई दर 1980 के बाद से सबसे ज्यादा है। यहां जून में महंगाई 9.1% पर पहुंच गई। इस इजाफे के बाद अमेरिका में मंदी की आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने फिलहाल आर्थिक सुस्ती की आशंका से इनकार किया है। वर फेड ने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई काबू में नहीं आने पर ब्याज दरों में फिर इजाफा किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक महंगाई को 2% तक लाना चाहता है।

RBI के फैसले पर एक्सपर्ट की राय

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के टऊ और CEO मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक ब्याज की दरें बढ़ाने के फैसले के बावजूद, RBI को लगता है कि महंगाई अपने कंफर्ट जोन से ऊपर रहेगी और उसने फाइनेंशियल ईयर-2023 के लिए अपने CPI महंगाई के अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा है।

RBI का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की GDP ग्रोथ 7.2% पर रहेगी। हम मानते हैं कि कच्चे तेल सहित कमोडिटी की कीमतें कम हो गई हैं और महंगाई अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि RBI अपनी आने वाली पॉलिसी मीटिंग में महंगाई के आंकड़ों के आधार पर अब ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपनाएगा।

साल में 0.5% का इजाफा हो सकता है

RBI पॉलिसी पर बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा, 'महंगाई और ग्रोथ दोनों पर पूवार्नुमानों में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद RBI ने स्पष्ट रूप से इंफ्लेशन पर आक्रामक रुख अपनाया है।

हम इस स्थिति में साल के दौरान एक और 50 bps (0.5%) हाइक की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अगली दो तिमाहियों में महंगाई 6% से ऊपर रहेगी। ग्रोथ पर RBI की टिप्पणी भी आश्वस्त करने वाली है क्योंकि ग्लोबल अरेना में डिस्टरबेंस के बावजूद ग्रोथ स्टेबल पाथ पर है।'





लेकिन ईरान में इससे आजादी के लिए सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं

भारत में हिजाब पर बवाल

आपको याद होगा साल 2021 के दिसंबर के महीने में कर्नाटक में हिजाब को बवाल मचा था। इस बवाल के चलते हिंसा भी देखने को मिली। इस मामले ने कुछ इस कद्र तूल पकड़ा कि यह मामला देश की राजनीति में बहस का कारण भी बना, लेकिन ईरान में हिजाब को लेकर एक नई बहस चल रही है। यहां महिलाएं बुरके का विरोध करने सड़कों पर उतर आयी हैं।

- ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो

भारत में हिजाब को लेकर मुस्लिम समुदाय कितना कट्टर है। इस बात का अंदाजा आप पिछले दिनों कर्नाटक में हिजाब को लेकर मचे बवाल को देखने के बाद लगा ही चुके होंगे।

हिजाब को लेकर यह मानसिकता भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी के देशों में भी बहुतायत से देखी जा सकती है। हिजाब को लेकर माना यह भी जाता है कि इसमें महिलाओं

की सुरक्षा छुपी है। यह हो भी सकता है। और क्योंकि यह मामला एक खास समुदाय विशेष की अपनी धार्मिक मान्यताओं का भी है तो इसमें धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इस मामले पर अभी बहस बाकी है।

वहीं, खास समुदाय के लोगों को भी इस बात को ठीक प्रकार से समझना चाहिए कि स्कूल, कॉलेज या कुछ सरकारी विभागों में एक कॉमन यूनिफॉर्म कोड होता है। जिसका मकसद सभी को एक समान महसूस करवाकर एक जैसी शिक्षा या सुविधा देना होता है। इसमें धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ड्रेस कोड की 'अवहेलना' कानून व्यवस्था खराब करना है। इस तरह के कार्य के लिए 'साधारण सजा' तक का प्रावधान है। अब यह तो रही देश की बात लेकिन वहीं, दूसरी ओर, ईरान में बुरखे को लेकर एक नयी बहस उठ रही है। यहां की महिलाएं बुरखे का विरोध कर रही है।

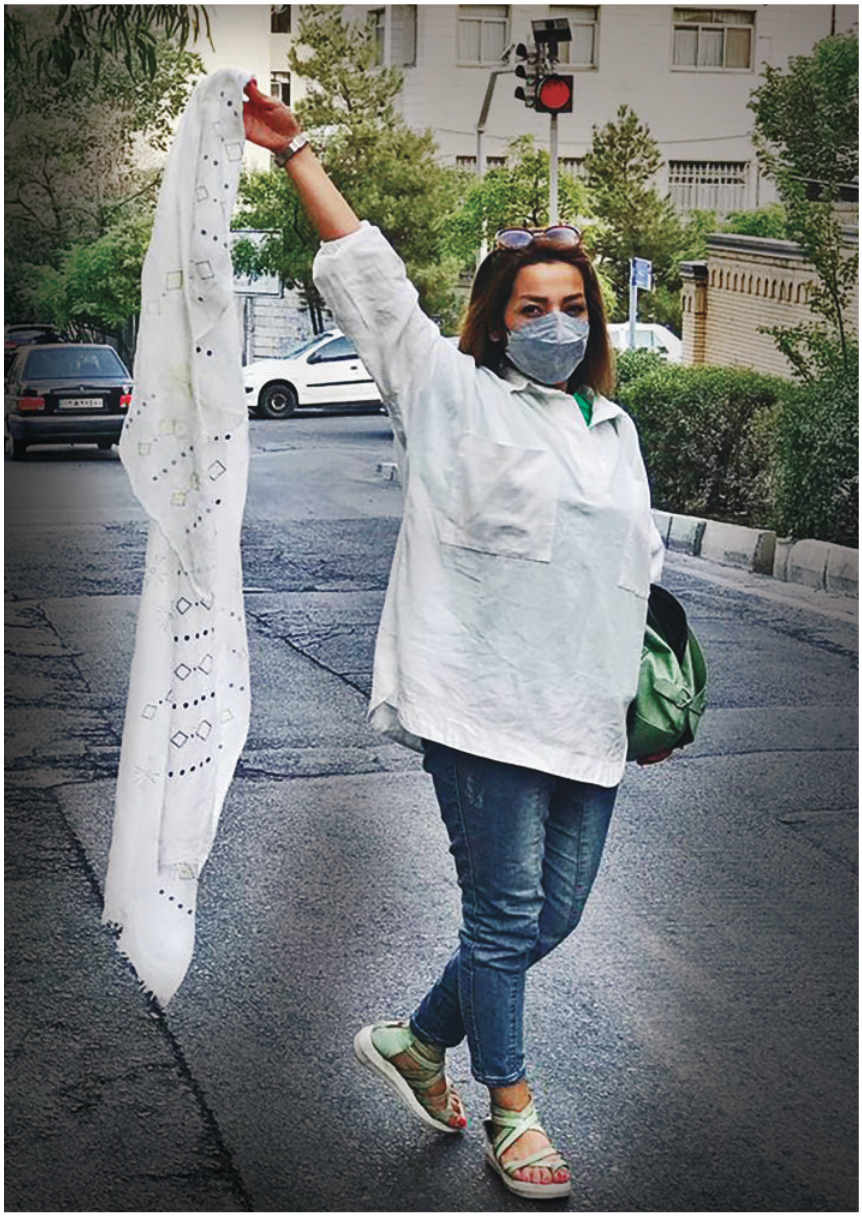

भारत में हिजाब बना राजनीति का अखाड़ा

पिछले साल दिसंबर की बात है भारत के कर्नाटक राज्य में मुस्लिम छात्राओं को यूनिफार्म में कालेज आने को कहा गया और हिजाब पहनकर कालेज में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कालेज में पढ़ने वाली छात्राएं एकसमान दिखें। लेकिन उस वक्त कट्टरपंथी ताकतों एवं वामपंथियों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। कट्टरपंथी मुस्लिम छात्राओं ने जहां इस फैसले के खिलाफ धरना दिया प्रदर्शन किया और अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी वहीं अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

ईरान में बुरखे के खिलाफ आंदोलन

वहीं, इस्लामिक देश ईरान में मुस्लिम महिलाओं ने पितृसत्तात्मक सोच से उपजे हिजाब से आजादी के लिए सड़कों पर उतरकर न केवल आवाज बुलंद की है बल्कि हिजाब को गलियों में फेंक दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब मुस्लिम बहुल देश में महिलाएं हिजाब से मुक्ति चाहती हैं तो भारत जैसे विविधता वाले देश में महिलाएं हिजाब पहनने के लिए इतनी कट्टर क्यों हैं।

सोशल मीडिया पर नंदिनी दास ने कहा है कि कुछ मानसिक रूप से बीमार मुल्ला कह रहे हैं कि मिया खलीफा मुस्लिम नहीं

है। सोफिया अंसारी भारतीय मुसलमान हैं और हिजाब नहीं पहनती हैं। उन्हें पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों की परवाह नहीं है। सऊदी अरब ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया। LoveJihad PFI की नीति है। BanPFI हम मुस्लिम महिलाओं के No2Hijab आंदोलन के साथ हैं। नंदिनी ने साथ ही कहा कि मिया खलीफा और राणा अय्यूब ने हिजाब नहीं पहना है, फिर तथाकथित भारतीय मुस्लिम विद्वान शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ आवाज क्यों उठाते हैं। ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ मार्च कर रही हैं, हिजाब के खिलाफ आंदोलन का हर जगह स्वागत है।

एक अन्य सोशल मीडिया यूजर धूलेंद्र रायका ने कहा कि ईरान में #No2Hijab चल रहा है और भारत में वामपंथी, इस्लामवादी #HijabisOurRight चला रहे थे। प्रियंका शर्मा ने लिखा है कि मोहतरमा राणा अय्यूब कुछ कहना नहीं है क्या। अविज राज सिंह ने कहा कि तथाकथित बुद्धिजीवी मुल्ला मौलवी महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वे समाज को भड़का रहे हैं #ShameOnyou.

ट्विटर पर एक अन्य यूजर अजय ने लिखा, इस्लामी देश ईरान की महिलाएं हिजाब से स्वतंत्रता चाहती हैं जबकि भारत में धर्मांतरित मुसलमान हर क्षेत्र में हिजाब चाहते हैं।

कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के अड़ियल रवैए से यह विवाद बढ़ा और बढ़ता ही गया। अब सवाल यही है कि दुनिया के एक हिस्से में महिलाएं इसे बोझ समझती हैं और इससे आजादी चाहती हैं तो फिर भारत में मुस्लिम महिलाएं हिजाब के समर्थन में क्यों खड़ी हैं। क्या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है। क्या इसके पीछे धर्म के नाम पर रोटी सेंकने वाले लोग हैं जिन्हें दुकान बंद होने का डर है।

कर्नाटक हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि क्लासरूम में हिजाब पहनने की अनुमति देने से 'मुसलमान महिलाओं की मुक्ति में बाधा पैदा होगी' और ऐसा करना संविधान की 'सकारात्मक सेकुलरिज्म' की भावना के भी प्रतिकूल होगा।



हिजाब से सुरक्षा का एहसास

एक तरफ ईरान की मुस्लिम महिलाएं हिजाब को बंधन समझती हैं और इससे आजादी चाहती हैं वहीं भारत में हिजाब के समर्थन में अजीब तर्क दिया जाता है कि इसे पहनने से सुरक्षा का एहसास होता है। इस तरह तो भारत में जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं उन्हें असुरक्षित महसूस करना चाहिए? यह तर्क न केवल असंगत प्रतीत होता है बल्कि इसके पीछे कट्टर मानसिकता का बोध कराता है।

हिजाब पहनने वाली बीए प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने डीडब्ल्यूडॉटकॉम से कहा था, 'उन्हें हिजाब से सुरक्षा का एहसास होता है और यह उनकी निजी पसंद है। हिजाब पहनने के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा है ना ही मेरे माता-पिता ने ऐसा करने के लिए कहा है। मैंने खुद ही हिजाब पहनना चुना है।' जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किस तरह से सुरक्षा का एहसास होता है तो उन्होंने कहा, 'जब मैं शहर में हिजाब पहनकर जाती हूं तो मुझे कोई नहीं देखता है।'

ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं

इस्लामिक देश ईरान में हिजाब का जबरदस्त विरोध हो रहा है। ईरानी महिलाएं हिजाब के विरोध में सड़कों पर हैं। यही नहीं वे पब्लिक में अपना नकाब हटाकर उसका



वीडियो भी बना रही हैं। ये महिलाएं हिजाब हटाने के वीडियो पोस्ट कर इस्लामिक रिपब्लिक के सख्त हिजाब नियमों का विरोध कर रही हैं।

हिजाब एवं शुद्धता दिवस का विरोध

ईरानी कानून के मुताबिक महिलाओं को सार्वजनिक तौर अपने बाल ढंकना अनिवार्य है। वैसे तो हिजाब को लेकर यहां अक्सर प्रदर्शन होते रहते हैं लेकिन 12 जुलाई को बड़ी संख्या में ईरानी महिलाओं ने देश भर में हिजाब विरोधी अभियान में भाग लिया। ईरान के अधिकारियों ने 12 जुलाई (मंगलवार) को 'हिजाब एवं शुद्धता दिवस' के रूप में घोषित किया था। इसी के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरीं।

हिजाब को गलियों में फेंक रही हैं ईरानी महिलाएं

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में महिलाओं के अलावा पुरुष भी ईरान के कानून के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। कुछ वीडियो में महिलाओं को स्कार्फ और शॉल को सड़कों पर फेंकते हुए देखा जा सकता है। महिलाएं बिना हिजाब के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानों में दिखाई दे रही हैं। वे खुले बालों में पब्लिक में घूम रही हैं।

सरकार ने हिजाब में महिलाओं को पेश किया

ईरान की सरकार ने हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए सरकारी टेलीविजन से 'हिजाब और शुद्धता' समारोह का एक वीडियो प्रसारित किया। इसमें 13 महिलाओं को हरे रंग के हिजाब और लंबे सफेद वस्त्र पहने हुए दिखाया गया था। वे महिलाएं कुरान की आयतें पढ़कर नृत्य कर रही थीं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो का जमकर मजाक उड़ाया गया।

ईरान में 1979 से अनिवार्य हुआ था हिजाब

ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद 9 वर्ष से अधिक उम्र की ईरानी महिलाओं और लड़कियों के लिए सार्वजनिक रूप से हिजाब अनिवार्य है। कई ईरानी महिलाओं ने वर्षों से शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और सरकारी आदेश के खिलाफ अपने मन के कपड़े पहनने पर जोर दिया है। ईरान में हिजाब पहनने से इनकार करने पर महिलाओं को जेल या फिर भारी जुमार्ने का सामना करना पड़ सकता है।

कई देशों जैसे फ्रांस में 18 साल की लड़कियों के सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने पर पांबदी है। इसके अलावा बेल्जियम, नीदरलैंड्स और चीन में भी हिजाब पहनने पर रोक है। भारत में कुल आबादी का लगभग 14 फीसद मुसलमान हैं और यहां सार्वजनिक तौर पर हिजाब या बुर्का पहनने पर कोई रोक नहीं है।

बहरहाल, हिजाब को लेकर भारत में बहस मुहाबिस का दौर चल ही रहा है। इसके अलावा भी एशिया के बहुत से देशों में हिजाब को लागू करने या फिर इसपर महिलाओं को आजादी देने को लेकर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन, ईरान में महिलाओं के द्वारा हिजाब का विरोध और पितृसत्ता के खिलाफ लामबंद होना वेशक इस बात की तस्दीक है कि दुनिया में और खासकर के ईरान में अब महिलाएं यह समझ रही है कि महिलाओं की आजादी भी इस दुनिया में जरूरी है। और शर्म और सुरक्षा दोनों ही कानून और राज्य, स्टेट या देश के मसले हैं जिन्हें देने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए एक ढाई गज के पर्दे को नहीं।

कैसे एक खास मिसाइल R9X हेलफायर से मारा गया अल जवाहिरी



अमेरिका की सीक्रेट मिसाइल, जिससे सिर्फ आतंकी मरते हैं, न विस्फोट न बेगुनाह मौतें, बालकनी में ही ढेर हुआ जवाहिरी; R9X हेलफायर को जानिए कैसे करती है यह दुश्मन का खात्मा

-रवीन्द्र कुमार

अ कायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को 2 मिसाइलें दाग कर मार गिराया है। हालांकि उस जगह पर धमाके का कोई निशान नहीं दिख रहा है, न ही कोई और कैजुअल्टी हुई। इसके बाद से यह चर्चा है कि अमेरिका ने कौन सी मिसाइल दागी जिससे विस्फोट भी नहीं हुआ और जवाहिरी मारा भी गया।

इसका जवाब है R9X हेलफायर मिसाइल, जिसे निंजा भी कहते हैं। इस मिसाइल में विस्फोटक के बजाय 6 रेजर जैसे ब्लेड लगे होते हैं जो टारगेट के टुकड़े-टुकड़े कर देता है। इसी सीक्रेट किलर मिसाइल से जवाहिरी को भी मारा गया है।

आईये सबसे पहले R9X हेलफायर निंजा मिसाइल के बारे में जानते हैं।

बाइडन प्रशासन के एक सीनियर अफसर ने 2022) करीब 6.18 बजे काबुल के शेरपुर में जवाहिरी बालकनी में टहल रहा था। उस वक्त 2 R9X हेलफायर मिसाइल आईं और जवाहिरी को मार गिराया। ये मिसाइल ड्रोन से दागी गईं थीं। इस हमले में न तो कोई विस्फोट हुआ, न कोई फैमिली मेंबर मारा गया और न आस-पास की इमारतों को कोई नुकसान हुआ।

दरअसल, R9X हेलफायर दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिसाइलों में से एक है। ये पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें विस्फोट नहीं होता, बल्कि 45 किलो वजनी मिसाइल में 6 धारदार ब्लेड्स लगे होते हैं। इससे बिना विस्फोट किए टारगेट को मारा जा सकता है। जवाहिरी को इसी मिसाइल से मारा गया। इस दौरान जवाहिरी के परिवार के अन्य सदस्यों को मामूली चोटें ही आई हैं।

ने R9X मिसाइल से हमले की रिपोर्ट की थी। इसमें बताया गया था कि मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, यमन और सोमालिया में बड़े आतंकियों को मारने के लिए किया गया। R9X को फ्लाइंग गिंसु भी कहा जाता है। यह एक जापानी चाकू होता है जिसे 1980 के दशक में टीवी विज्ञापनों में देखा जाता था। विज्ञापन में दिखाया जाता था कि चाकू टिन की बनी कैन आदि को कतर देता था और तब भी बेहद नुकीला और तेज बना रहता था।

सटीक निशाना, टारगेट पर ही करती है अटैक

मिसाइल से कार में बैठा टारगेट ही मरेगा, ड्राइवर सेफ रहेगा

रिपोर्ट में बताया गया है कि R9X मिसाइल अपने टारगेट पर पूरी सटीकता के साथ हमले करता है। जैसे कि किसी

कार में यदि किसी टारगेट को निशाना बनाया जाता है तो मिसाइल सिर्फ टारगेट को मारेगी और कार के ड्राइवर को कोई चोट भी नहीं आएगी। मिसाइल के ब्लेड इतने पैने होते हैं कि ये बिल्डिंगों और कार की छतों को काट सकते हैं।

खासियत : कोई बेगुनाह नहीं मारा जाता

R9X हेलफायर मिसाइल टारगेटेड किलिंग के लिए मशहूर है। इससे आसपास बहुत कम कैजुअल्टी होती है, यानी आम नागरिकों की जान जाने का खतरा नहीं होता है।

कब बनी : 11 साल पहले ओबामा के समय बनाई गई

2011 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तब इस मिसाइल को बनाया गया था। ओबामा ने मिडिल ईस्ट में ड्रोन हमलों में कैजुअल्टी को कम करने के लिए इस मिसाइल को बनाने का आदेश दिया था। विस्फोटक नहीं होने के कारण इसे निंजा मिसाइल भी कहा जाता है।

R9X मिसाइल को CIA और अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थ्राप गुम्मन ने मिलकर बनाया है। अब तक एक दर्जन से ज्यादा मामलों में टारगेटेड किलिंग के लिए इसका यूज किया जा चुका है।

बड़े हमले जहां R9X मिसाइल का इस्तेमाल हुआ

2019 : R9X के जरिए 'जमाल अल-बदावी' को मारा गया था

यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले जनवरी 2019 की बात है। अमेरिका ने इसी R9X मिसाइल के जरिए अपने सबसे बड़े दुश्मन में से एक आतंकी जमाल अल-बदावी को मार गिराया था। दरअसल, आतंकी जमाल अल-बदावी साल 2000 में यमन पोर्ट पर 17 अमेरिकी सेना पर हुए हमले में शामिल था। इस हमले में अमेरिकी सेना के सभी जवान मारे गए थे। अमेरिका ने अपने जवानों की बेरहमी से हुई हत्या के करीब 19 साल बाद R9X मिसाइल के जरिए बदला लिया था।

2017 : 'अहमद हसन अबू अल-खैर अल-मसरी' भी बना R9X का शिकार

अब बात फरवरी 2017 में घटी उस तीसरी घटना की जब अमेरिका ने R9X मिसाइल से दुनिया के एक और खूंखार आतंकी का खात्मा किया था। मिस्र का रहने वाला अहमद हसन अबू अल-खैर अल-मसरी इस वक्त आतंकी संगठन अल कायदा का नंबर 2 नेता था। इसे अमेरिका ने सीरिया के इदलिब प्रोविंस में R9X मिसाइल से हमला कर मार गिराया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अंजाम दिया था। हालांकि CIA इस तरह के किसी हमले की बात को स्वीकार करने से बचता रहा है।

2017 में R9X मिसाइल से जब अल मसरी को मारा गया तो वह अपनी कार से कहीं जा रहा था। हमले की तस्वीरों में देखा गया कि कार की छत पर एक बड़ा छेद हो गया था और कार के अंदर सवार लोग व इंटीरियर सबका सब ऐसे कतर दिया गया था जैसे कैंची से काटा गया हो। इसके बावजूद कार का अगला और पिछला हिस्सा सलामत थे।

2017 में R9X मिसाइल से जब अल मसरी को मारा गया तो वह अपनी कार से कहीं जा रहा था। हमले की तस्वीरों में देखा गया कि कार की छत पर एक बड़ा छेद हो गया था और कार के अंदर सवार लोग व इंटीरियर सबका सब ऐसे कतर दिया गया था जैसे कैंची से काटा गया हो। इसके बावजूद कार का अगला और पिछला हिस्सा सलामत थे।

2021 : 13 जवानों के मारे जाने पर अमेरिका ने किया R9X का इस्तेमाल

अगस्त 2021 में अमेरिका ने इसी R9X मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान के नांगरहार प्रोविंस में 2 कुख्यात ISIS आतंकियों को मार गिराने के लिए किया था। अमेरिकी सेना ने MQ-9 रीपर ड्रोन के जरिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने ये हमला हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वर जवानों पर हुए हमले के जवाब में किया था। इस हमले में 13 अमेरिकी जवान मारे गए थे।

अमेरिका ने अल कायदा प्रमुख जवाहिरी को मारने से पहले अंतिम बार जून 2022 में सीरिया के इदलिब शहर में भी R9X हेलफायर मिसाइल का यूज किया था। उस दौरान हुर्रस अल दीन के आतंकी अबू हमजा अल यमनी को इस मिसाइल से मारा गया था।

अमेरिका ने अल कायदा प्रमुख जवाहिरी को मारने से पहले अंतिम बार जून 2022 में सीरिया के इदलिब शहर में भी R9X हेलफायर मिसाइल का यूज किया था। उस दौरान हुर्रस अल दीन के आतंकी अबू हमजा अल यमनी को इस मिसाइल से मारा गया था।

72 साल पहले से अमेरिका के पास है 'निंजा' की तरह घातक हथियार

आज जिस खतरनाक टारगेटेड मिसाइल निंजा यानी R9X के जरिए अमेरिका ने आतंकी अयमान अल-जवाहिरी को मार गिराया है, उस तरह के हथियार के इस्तेमाल की शुरूआत अमेरिका में 72 साल पहले ही हो गई थी।

1950 के दशक में कोरिया और वियतनाम जंग के दौरान अमेरिकी सेना के जवानों ने इसी तरह का टारगेटेड किलिंग हथियार 'लेजी डॉग' बनाया था। ऐसा इसलिए, ताकि बिना बड़ा विस्फोट किए सिर्फ टारगेट को मारा जा सके। जंग के दौरान अमेरिका 'लेजी डॉग' बम का इस्तेमाल एयरफोर्स की मदद से करता था। हालांकि करीब 10 साल बाद ही अमेरिका ने 1960 में इस तरह के बम को बनाना बंद कर दिया था।

स्मार्ट सिटी तो बना ली लेकिन स्मार्ट सिटी से निकलने वाले कूड़े का क्या इंतजाम है



भारत देश तेजी से तरक्की कर रहा है। स्मार्ट सिटी बन रही हैं। लेकिन देश में अभी तक घरों से निकलने वाले कूड़े के निष्पादन को लेकर कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि हम स्मार्ट सिटी की कल्पना तो कर रहे हैं लेकिन इससे निकलने वाले कूड़े को लेकर चिंतित नहीं है।

ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो

दिल्ली में जब आप उत्तर प्रदेश की ओर से प्रवेश करते हैं तो आपके दांये हाथ पर गाजीपुर में कूड़े का स्वागत करता है। इसी तरह से पंजाब-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर भलस्वा लैंडफिल साइट पर आप दम



दिल्ली ही नहीं बल्कि देश में अभी तक कूड़े कचरे के निष्पादन के लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है। कूड़ा करकट उठाने वाले मजदूर कूड़े को छांट कर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बेचते हैं। वह फैक्ट्रियां छांटे गए कूड़े को रिसाइकिल करती हैं।



पहाड़ तेज बदबू के साथ साधन को मजबूर होते हैं।

राजधानी दिल्ली। भारत की शान। देश के प्रमुख भी यहीं रहते हैं लेकिन दिल्ली तीन कूड़े के पहाड़ों से घिरी हुई है। दिल्ली में जब आप उत्तर प्रदेश की ओर से प्रवेश करते हैं तो आपके दांये हाथ पर गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ तेज बदबू के साथ स्वागत करता है। इसी तरह से पंजाब-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर भलस्वा लैंडफिल साइट पर आप दम साधने को मजबूर होते हैं। यानी सांस रोककर यह एरिया पार करने की कोशिश करते हैं और ठीक दिल्ली के ओखला में कूड़े के पहाड़ और उनपर उड़ती चील और कौए आपकी नजर आकाश की ओर खींच लेते हैं।

यह नजारा गर्मी में और भी बदबूदार हो जाता है। क्योंकि गर्मियों में अक्सर इन तीनों साइट पर आग लग जाती है। आग लगने से उठने वाले धुएं और बदबू स्मार्ट सिटी का तमगा उतार कर जमीन पर पटक देती है। लगी आग और बदबू यह भी अहसास करवाती है कि दिल्ली कहने को राजधानी है क्योंकि यहां कूड़े के निष्पादन को लेकर सरकार की तैयारी सिर्फ कागजों पर ही है।

एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 10 मीट्रिक टन कचरा हर रोज निकलता है। इसमें प्लास्टिक, कागज और गीला कचरा भी शामिल होता है। हालांकि इस कचरे के निपटारे के लिए दिल्ली एमसीडी रात दिन काम करती है। लेकिन वह काम सिर्फ कचरा बटोरने और लैंडफिल साइट पर पहुंचाने का है।

दिल्ली ही नहीं बल्कि देश में अभी तक कूड़े कचरे के निष्पादन के लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है। कूड़ा करकट उठाने वाले मजदूर कूड़े को छांट कर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बेचते हैं। वह फैक्ट्रियां छांटे गए कूड़े को रिसाइकिल करती हैं। जिसमें प्लास्टिक और मेटल के साथ गत्ता, कागज और दूसरा कूड़ा शामिल होता है।

जी हां, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राजधानी दिल्ली तीन ओर से तीन कूड़े के पहाड़ों से घिरी हुई है। इनमें भलस्वा लैंडफिल साइट, ओखला और गाजीपुर कूड़े का पहाड़ शामिल हैं। ये तीनों कूड़े के पहाड़ दिल्ली के तीन अलग-अलग हिस्सों में है लेकिन दिल्ली का प्रदूषण और दिल्ली को बीमार करने के लिए काफी हैं।

यहां हम आपको बताते चलें कि, साल 2022 के मई जून महीने में भलस्वा लैंडफिल साइट में आग लगने से एक बार फिर कूड़े के पहाड़ों की ओर सभी का ध्यान गया था। यह कूड़ा 6 दिन तक लगातार जलता रहा। इसमें से जानलेवा धुआं और जहरीली गैसें लगातार निकल रही थीं। जो न केवल आसपास के इलाके में बल्कि पूरी दिल्ली की हवा को दूषित कर रही थी। स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों की मानें तो ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली के वातावरण और हवा को जहरीली बनाने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

दिल्ली के तीन इलाकों में बने इन कूड़े के पहाड़ नुमा ढेर में हर साल ही आग लगने की सूचनाएं मिलती हैं। दिल्ली की गंदगी को समेटे इन ढेरों में लगातार मीथेन गैस बनती है। इस वजह से भी यहां आग लगने की घटनाएं होती हैं। दिल्ली में सामान्य जगहों पर भी आग लगाने में पाबंदी है लेकिन कई सौ एकड़ में फैले इन पहाड़ों में जब तब आग लगती है और जहरीली गैसें वायुमंडल में तैरने लगती हैं। खास बात है कि दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों के बावजूद ये कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं।

सर्दी में पराली, गर्मी में कूड़े के ढेर...

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में वायु प्रदूषण विशेषज्ञ विवेक चट्टोपाध्याय बताते हैं कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर काफी ज्यादा मात्रा में कूड़ा जल रहा है। इस दौरान धुआं काफी जहरीला होता है। उसमें पार्टिकुलेट मैटर तो होगा ही। इसमें प्लास्टिक जलाने से पैदा होने वाले विषाक्त तत्व भी होते हैं। इससे आसपास का इलाका तो जहरीला हो ही रहा है, वहीं हवा का रुख जिस तरफ है ये धुआं उधर पर जाकर इकठ्ठा हो रहा है। यह धुआं सांस के माध्यम से लोगों के शरीर में जा रहा

कूड़े के ढेर से निकलने वाला धुआं और गैसें कार्बन डाई ऑक्साइड, डाईऑक्सीन, फ्यूरॉन, कार्बन मोनो ऑक्साइड आदि बहुत जहरीली होती हैं जो कैंसर आदि बीमारियों की जन्मदाता होती हैं।



है। सर्दी में प्रदूषण के लिए पंजाब आदि राज्यों को लेकर कहा जाता है लेकिन यह दिल्ली का खुद का मुद्दा है, जिसका समाधान होना काफी जरूरी है।

स्वास्थ्य पर ये पड़ रहा है प्रभाव

विवेक कहते हैं कि कूड़े के ढेर में आग लगी है तब तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, वहीं अगर आग नहीं भी लगी है तो भी ये दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। कूड़े के ढेर का दो तरह से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। एक दीर्घकालिक और एक अल्पकालीन यानी थोड़े से समय में ही प्रभाव दिखाई देने लगता है। कूड़े के ढेर का शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन प्रभाव ये हैं कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। दम घुटता है। जिन लोगों को दमा या अस्थमा आदि की शिकायत होती है, उनको काफी परेशानी हो सकती है। फेफड़ों को नुकसान हो सकता है।

कूड़े के ढेर से निकलने वाला धुआं और गैसें कार्बन डाई ऑक्साइड, डाईऑक्सीन, फ्यूरॉन, कार्बन मोनो ऑक्साइड आदि बहुत जहरीली होती हैं जो कैंसर आदि बीमारियों की जन्मदाता होती हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने वाले लोगों में कैंसर की बीमारी ज्यादा देखी जा सकती है।

सामान्य जन-जीवन प्रभावित रहता है

कूड़े को जलाने से टॉक्सिक रसायन सहित कार्बन कण, बेंजीन, पारा, वैनेडियम आदि विषैले तत्व निकलते हैं।

ये विषैली गैसें दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए भी नुकसानदायक हैं।

कूड़े के ढेर से लगातार गंदा पानी और तरल पदार्थ रिसते रहने से भूगर्भीय जल प्रदूषित हो जाता है। जिसकी वजह से आसपास के इलाके में भूगर्भीय जल भी संक्रमित और बीमारियों का वाहक हो जाता है। ऐसी जगहों पर रह पाना मुश्किल हो जाता है। कूड़े से निकलने वाली गैसों से वायुमंडल प्रदूषित होता है।

इससे लोगों को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती।

कूड़े के ढेर के आसपास की जमीनों में भी जहरीले तत्व पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उन खेतों या क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें भी जहरीली या विषैली हो जाती हैं और खाने योग्य नहीं रहतीं।

विवेक की माने तो कूड़ा किसी भी शहर की मजबूरी तो है ही। क्योंकि अगर शहर होगा तो कूड़ा भी होगा। लेकिन इसके निस्तारण की व्यवस्था करना बेहद आवश्यक है।

कूड़े के निष्पादन के लिए कई बार गंभीर चचाएं भी हुई है लेकिन, नतीजा सिफर ही रहा है। अब देश के लोगों को इस तरफ इसलिए भी ध्यान देना होगा क्योंकि अगर शहर बढ़ेगा तो कूड़ा भी बढ़ेगा। और जब कूड़ा बढ़ेगा और अगर उसका निस्तारण सही तरीके से नहीं होगा तो वह शहर को प्रदूषित करेगा। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि शहर के विकास के साथ-साथ योजना बनाने वाली सरकार और संस्थाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि शहर के कूड़े का खात्मा किस तरह से किया जाए। ताकि शहर में लोग साफ सुथरी हवा में सांस ले पाए।





वंदे भारत एक्सप्रेस में नहीं मिलेगा नॉनवेज, बनी देश की पहली 'सात्विक' ट्रेन

भारतीय रेलवे ने इसकी शुरुआत वंदे भारत एक्सप्रेस से की है। ट्रेनों में खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने वाली आईआरसीटीसी और सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। यह ट्रेन नई दिल्ली से कटरा यानी माता वैष्णो देवी जाने वाली ट्रेन है।

-ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो

नई दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में नॉनवेज खाने और ले जाने पर पाबंदी होगी। क्योंकि वंदे भारत ट्रेन देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसे सात्विक सर्टिफिकेट दिया गया है। यह पूरी ट्रेन अब पूरी तरह से हाइजेनिक और वेजिटेरियन है।

भारतीय रेलवे ने इसकी शुरूआत वंदे भारत एक्सप्रेस से की है। ट्रेनों में खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने वाली आईआरसीटीसी और सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। इसी के तहत आईआरसीटीसी ने वंदे भारत से सात्विक ट्रेन बनाने की शुरूआत कर दी है। अब धीरे-धीरे अन्य धार्मिक स्थलों को जाने वाली अन्य ट्रेनों को भी सात्विक बनाया जाएगा।

आईआरसीटीसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस ट्रेन के अलावा अन्य धार्मिक स्थानों पर जाने वाली ट्रेनों में नॉनवेज खाने पर प्रतिबंध होगा। क्योंकि इन ट्रेनों में सफर करने वाले अधिकांश यात्री ऐसे होते हैं, जो धार्मिक यात्रा पर होने के चलते यात्रा के दौरान पूरी तरह से सात्विक खाना पसंद करते हैं। इसके बाद सामान्य ट्रेनों को भी सात्विक बनाया जाएगा।

वहीं दूसरी ओर कई यात्री ट्रेनों में सफर के दौरान परोसे जाने वाला खाना शुद्धता के साथ सफाई के चलते खाना पसंद नहीं करते हैं। यात्रियों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि यह खाने बनाने के दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखा गया है या नहीं।

वेज और नॉनवेज को अलग-अलग पकाया गया है या नहीं। या फिर खाना तैयार करने से लेकर सर्व करने क्या प्रक्रिया है। यात्रियों की इन्हीं सभी शंकाओं को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने सात्विक ट्रेन की शुरूआत की है। जिसमें सभी यात्रियों को शुद्ध शाकाहारी खाना ही दिया जाएगा।

सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन को सात्विक का सर्टिफिकेट देने से पहले कई तरह की प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। इसमें खाना बनाने की विधि, किचन, परोसने और सर्व करने के बर्तन, रखने का तरीके की जांच की गई। सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया गया है।



चीन के लिए ताइवान पर जीत आसान नहीं

गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं 35 लाख ताइवानी

जंग के लिए पहले से तैयार की 5 पॉइंट स्ट्रैटजी, ताइवान पर जीत के लिए चीन की क्या है रणनीति

चीन की तमाम धमकियों के बावजूद नैंसी पेलोसी ताइवान आई और पूरा एक दिन गुजारकर वापस चली गई। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि पेलोसी की यात्रा से बौखलाया चीन अब ताइवान पर हमला भी कर सकता है। चीनी सेना ने ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी है। आईये जानते हैं अगर जंग हुई तो ताइवान खुद को चीन की विशाल सेना से कैसे बचाएगा?

सबसे पहले जानिए कि एक्सपर्ट युद्ध की आशंका क्यों जता रहे हैं

-ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो

ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर डॉनल्ड रॉथवेल डी डब्ल्यू से कहते हैं कि नैंसी पेलोसी का ताइवान जाना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व को चुनौती है। इसी साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस होनी है। जिसमें शी जिनपिंग लगातार तीसरा राष्ट्रपति कार्यकाल पाने का दावा करेंगे। ऐसे में पेलोसी की यात्रा शी के दावे को कमजोर करने की है, इसलिए वह इस कदम का कड़ा जवाब दे सकते हैं। पेलोसी के जाते ही चीन ने नॉर्थ, साउथ-वेस्ट और साउथ-ईस्ट में ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र

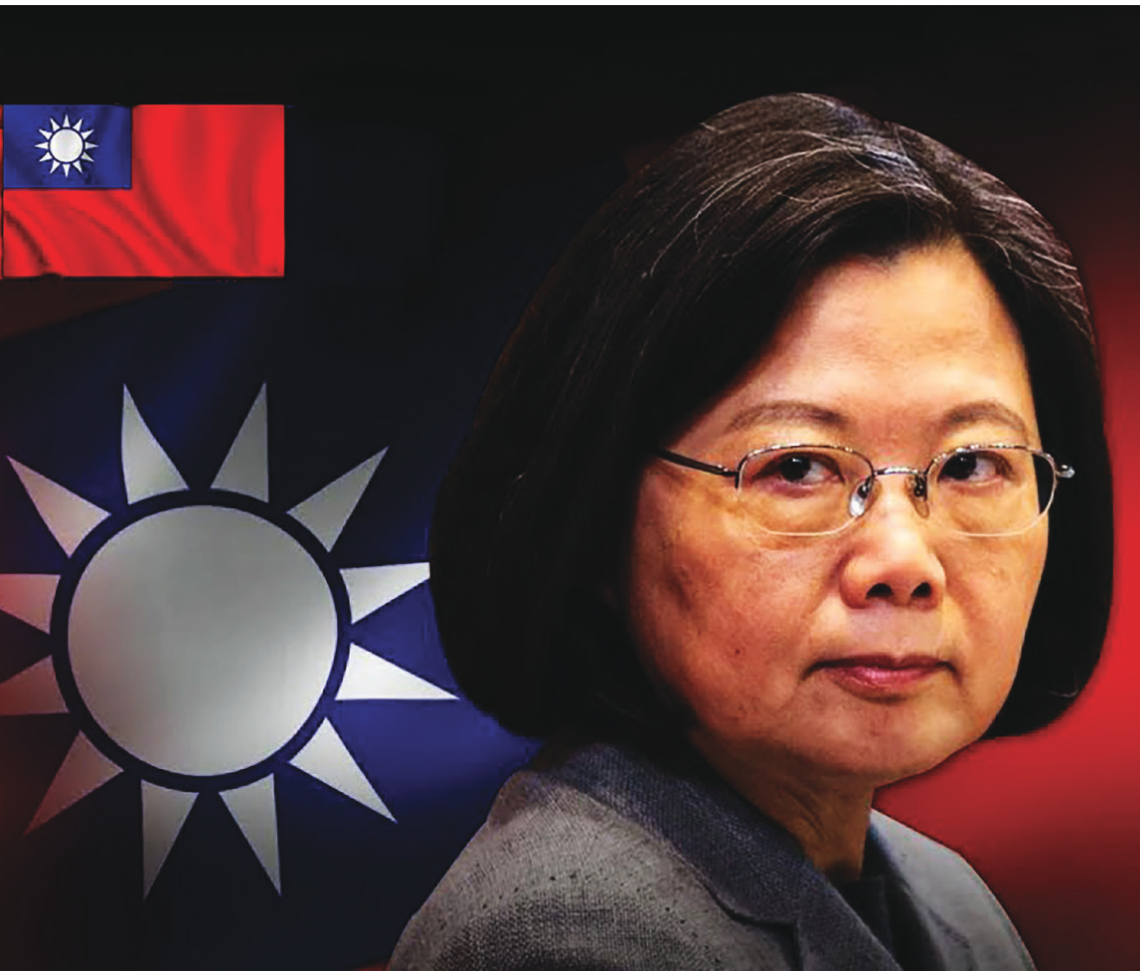

में मिलिट्री ड्रिल, यानी सैन्य अभ्यास की घोषणा कर दी है। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा है कि असली हथियारों और गोला-बारूद से ये अभ्यास इस पूरे हफ्ते तक किया जाएगा।PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल शी यी ने कहा कि सैन्य अभ्यास के दौरान लॉन्ग रेज लाइव फायर शूटिंग की जाएगी। साथ ही मिसाइल का भी टेस्ट होगा। इस तुलना में ताइवान भले ही कमजोर लग रहा हो, लेकिन उसे जीतना आसान नहीं होगा। ताइवान ने जंग की स्थिति में 5 स्ट्रैटजी बना रखी हैं। आइए एक-एक करके समझते हैं...

स्ट्रैटजी 1 : चीन ने हमला किया तो अमेरिका मदद करेगा

ताइवान को कुछ ही देशों ने मान्यता दी है। ताइवान को ज्यादातर देश चीन का हिस्सा मानते हैं। अमेरिका का भी ताइवान के साथ आधिकारिक रूप से राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन अमेरिका ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत उसे हथियार बेचता है। इस कानून में कहा गया है कि वो ताइवान की आत्मरक्षा के लिए जरूरी मदद देगा।

अक्टूबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान का बचाव करेगा। यह अमेरिका के पुराने रुख से अलग लाइन थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया था कि क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा तो बाइडन ने कहा, 'हां, ऐसा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।' बाद में व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस टिप्पणी को पॉलिसी में बदलाव के तौर पर नहीं लेना चाहिए।

स्ट्रैटजी 2 : पाकुर्पाइन स्ट्रैटजी से दुश्मन के लिए जंग को महंगा और कठिन बना दो

चीन और ताइवान के बीच तनाव ऐतिहासिक है। 1940 के दशक में गृहयुद्ध के दौरान चीन और ताइवान अलग हुए थे। उसके बाद से ताइवान खुद को स्वतंत्र देश कहता है। जबकि, चीन उसे अपने प्रोविंस के तौर पर देखता है और जरूरत पड़ने पर बल पूर्वक मिला लेने की बात करता है। यानी ताइवान पर चीन के हमले का खतरा दशकों से बना हुआ है।

ताइवान ने चीन जैसी विशाल शक्ति से निपटने के लिए एसिमिट्रिक वॉरफेयर

के मेथड को अपनाया है। इसे पाकुर्पाइन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। इसका उद्देश्य हमले को दुश्मन के लिए ज्यादा से ज्यादा कठिन और महंगा बनाना होता है।

ताइवान ने एंटी-एयर, एंटी-टैंक और एंटी-शिप हथियारों और गोला-बारूद के बड़े भंडार को इकट्ठा कर रखा है। इसमें ड्रोन और मोबाइल कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल यानी CDCM जैसे कम लागत वाले युद्धपोत शामिल हैं। ये चीन के महंगे नेवल शिप और नेवल इक्विपमेंट को नष्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं।

स्टील्थ फास्ट-अटैक क्राफ्ट्स और मिनिएचर मिसाइल असॉल्ट बोट वैसे तो सस्ते होते हैं, लेकिन ये काफी प्रभावी मिलिट्री इक्विपमेंट हैं। इन्हें ताइवान के बंदरगाहों में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बीच फैलाया जा सकता है। समुद्री माइंस और फास्ट माइन लेइंग शिप किसी भी हमलावर नौसेना के लैंडिंग ऑपरेशन को जटिल बना सकते हैं।

ताइवान की सबसे विशेष सैन्य यूनिट अफ्ढ में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग 10 हफ्ते चलती है। इन जवानों को ज्यादातर समय समुद्र या स्विमिंग पूल में गुजारना होता है। वे पूरी वर्दी में तैरने से लेकर लंबे समय तक पानी के अंदर सांस रोकने जैसे स्किल्स सीखते हैं। कई बार उन्हें हाथ-पांव बांधकर पानी में फेक दिया जाता है।

ताइवान की सबसे विशेष सैन्य यूनिट अफ्ढ में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग 10 हफ्ते चलती है। इन जवानों को ज्यादातर समय समुद्र या स्विमिंग पूल में गुजारना होता है। वे पूरी वर्दी में तैरने से लेकर लंबे समय तक पानी के अंदर सांस रोकने जैसे स्किल्स सीखते हैं। कई बार उन्हें हाथ-पांव बांधकर पानी में फेक दिया जाता है।

स्ट्रैटजी 3 : मल्टीलेयर्ड सी डिफेंस से चीन की हर फ्लीट पर नजर

ताइवान चारों तरफ समुद्र से घिरा है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को बड़ी संख्या में सैनिकों, बख्तरबंद वाहन, हथियार, गोला-बारूद, फूड, मेडिकल सप्लाई और फ्यूल को उस पार ले जाने की जरूरत होगी। यह केवल समुद्र से ही संभव है, क्योंकि एयरलिफ्ट और विमानों के बेड़े में सीमित क्षमता होती है।

ताइवान के इलाके में द्वीपों की एक श्रृंखला भी है। इनमें से कुछ चीनी तटों के पास हैं। इन द्वीपों पर पहले से लगे निगरानी इक्विपमेंट चीन के तटों से चलने वाले पहले फ्लीट्स या बेड़े का पता लगा सकते हैं। इससे ताइवान की सेना को मल्टीलेयर्ड सी डिफेंस के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

इससे पहले कि PLA के जवान ताइवान की जमीन पर उतरें और ऑपरेशन शुरू करें, उन्हें ताइवान की समुद्री माइंस, फास्ट अटैक क्राफ्ट और मिसाइल असॉल्ट बोट के साथ लैंड बेस्ड नौसैनिकों का भी सामना करना पड़ेगा। इससे PLA की स्थित काफी कमजोर होगी।



स्ट्रैटजी 4 : गुरिल्ला युद्ध के लिए हर 6 में से एक ताइवानी तैयार

यदि मल्टीलेयर्ड सी डिफेंस को भेदकर चीन के सैनिक ताइवान पहुंच भी जाते हैं, तो उसने अपने शहरों को गुरिल्ला युद्ध के लिए भी तैयार कर रखा है। ताइवान मैन-पोर्टेबल एयर-डिफेंस सिस्टम यानी MANPADS और



मोबाइल एंटी-आर्मर हथियार जैसे कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी लक्टअफर का यूज शहरी लड़ाई में कर सकता है। साथ ही बिल्डिंग्स को बैरक में बदल सकता है। RAND फाउंडेशन की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक, ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं। यह संख्या ताइवान की आबादी का 15% है यानी हर 6 में से एक व्यक्ति इससे जुड़ा है। रूस ने इस साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था, तब से ताइवानियों के बीच गन ट्रेनिंग की दर तेजी से बढ़ी है। राजधानी ताइपे के पोलर लाइट ट्रेनिंग सेंटर के CEO मैक्स चियांग कहते हैं कि बहुत से लोग जिन्होंने अपने जीवन में कभी गन नहीं देखी थी, वे इसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं।

ताइवान चारों तरफ समुद्र से घिरा है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को बड़ी संख्या में सैनिकों, बख्तरबंद वाहन, हथियार, गोला-बारूद, फूड, मेडिकल सप्लाई और फ्यूल को उस पार ले जाने की जरूरत होगी।

पिछले 3 महीनों में ताइवान में सभी उम्र और व्यवसायों के लोगों में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग में रुचि बढ़ी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश के टूर गाइड से लेकर टैटू आर्टिस्ट तक लगभग हर कोई विशेष परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए शूटिंग सीख रहा है। पिछले 3 महीनों में ताइवान में सभी उम्र और व्यवसायों के लोगों में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग में रुचि बढ़ी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश के टूर गाइड से लेकर टैटू आर्टिस्ट तक लगभग हर कोई विशेष परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए शूटिंग सीख रहा है।

स्ट्रैटजी 5 : डिफेंस सिस्टम से डिफेंड

युद्ध के समय ताइवान की टैक्टिस अपने डिफेंस सिस्टम जैसे कि एयरक्रॉफ्ट और एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम को बचाने की होगी। इन्हीं डिफेंस सिस्टम से ताइवान चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर खत्म कर सकता है। पिछले कुछ सालों से ताइवान अमेरिका से दर्जनों एडवांस फाइटर जेट खरीदे हैं। साथ ही खुद से स्वदेशी AIDC F-CK-1 चिंग कुओ फाइटर जेट बनाया है।

ताइवान ने अपने एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले बेस में रखा है। साथ ही पायलट्स को एयरपोर्ट्स पर बमबारी होने की स्थिति में हाइवे पर एयरक्रॉफ्ट उतारने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही अमेरिका ने युद्ध की स्थिति में ताइवान को डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस सपोर्ट देने की बात कही है। इन सभी उपायों से ताइवान को चीन को यह संदेश देने में मदद मिलेगी कि यदि युद्ध छिड़ता है, तो यह लंबा, महंगा और काफी खून-खराबे वाला होगा।

अलविदा शिंजो आबे, आप बहुत याद आएंगे

शिंजो आबे का नाम उन नेताओं में शामिल है जिन्हें हम ह्यस्टेट्समैनह्ल कहते हैं। यह इसलिए भी है कि दुनिया में नेता तो बहुत से होते हैं लेकिन ह्यराजनेताह्ल कम ही होते हैं। राजनेता से यहां यह मतलब है कि वह नेता जिसका प्रभाव न सिर्फ अपने देश में बल्कि सारी दुनिया पर हो। ऐसे ही थे शिंजो आबे जिन्होंने क्वाड की नींव रखी। शिंजो आबे ने चीन को गैर कानूनी तरीके से आगे बढ़ने से रोका साथ ही सारी दुनिया के सामने एक नयी मिसाल भी पेश की। अब शिंजो आबे इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन, उनकी यादे सदा दुनिया की राजनीति में जिंदा रहेंगी। ऑब्जर्वर डॉन शिंजो आबे को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अलविदा शिंजो, आप बहुत याद आएंगे।

रवीन्द्र कुमार

अलविदा शिंजो, लेकिन आप हमेशा भारत के दिल में रहेंगे। क्योंकि आप न सिर्फ अपने देश के बल्कि भारत के भी चहेते नेता थे। आप को भारत ने पदमविभूषण दिया तो आपने भारत को बुलेट ट्रेन से नवाजा। इतना ही नहीं आपने इस बात को समझा की अगर दुनिया में चीन की बढ़ती ताकत को अगर ब्रेक लगानी है तो वह भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान मिलकर ही लगा सकते हैं। आपने क्वाड की स्थापना की जिसके बाद चीन के न सिर्फ दांत खट्टे हुए बल्कि आपकी ख्याति सारी दुनिया में उन चुनिंदा नेताओं के रूप में फैली जिन्हें राजनीति के पटल पर 'स्टेट्समैन' कहा जाता है।

शिंजो आबे आपका लोहा सारी दुनिया ने माना। आज हमारे बीच शिंजो आबे नहीं है। लेकिन उनकी बहुत सी बाते और काम ऐसे हैं जिनसे भारत की राजनीति सीधे तौर पर प्रभावित रही। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी घनिष्ठता या फिर भारत में बुलेट ट्रेन लाने की योजना दोनों से ही भारत और जापान के बीच रिश्ते मजबूत करने में सहायक रहे। हालांकि यह बात भी सही है कि जापान के साथ दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से हमारे रिश्ते काफी प्रागढ़ हैं। जापान ने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद किसी भी तरह के युद्ध में हिस्सा लेना से न सिर्फ मना किया बल्कि दुनिया को भी शांति का संदेश दिया। भारत के साथ जापान के रिश्तों में प्रागढ़ता दूसरे विश्वयुद्ध के बाद बढ़ी। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का कार्यकाल के दौरान ही भारत जापान के बीच रिश्तों में मधुरता लगातार बढ़ी। यह सिलसिला आगे भी बढ़ता रहा और मौजूदा



प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने भारत जापान के रिश्ते को और मजबूत किया।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्मविभूषण से सम्मानित किया।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत ने पद्मविभूषण से भी नवाजा। यह सम्मान देकर भारत ने न सिर्फ जापाना के साथ अपनी मैत्री को आगे बढ़ाया बल्कि उसे और मजबूत भी किया। इस पुरस्कार के बाद जापान और भारत के रिश्ते को मजबूती तो मिली ही साथ ही दोनों देशों के बीच परस्पर मेलमिलाप भी बढ़ा।

चीन के प्रभाव को कम करने में बेहद असरदार फॉमूर्ला है क्वाड

भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर क्वाड की स्थापना शिंजो आवे ने की। क्वाड की स्थापना का मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव और सैन्य ताकत का मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाया गया। हालांकि क्वाड का प्रस्ताव काफी समय से लंबित था लेकिन आबे के प्रयासों से इसे आकार दिया गया था।

2007 में शिंजो आबे ने दिया था क्वाड का प्रस्ताव

साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ऐसे संगठन का प्रस्ताव दिया जिसमें हिन्द-प्रशांत समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश शामिल हो सके। 2007 में शुरू होने के बाद क्वाड अगले 10 सालों तक यानी 2017 तक निष्क्रिय रहा। 2017 में जब इस संगठन को फिर से तैयार किया गया तब इसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना था। 2019 में भी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियो की बैठक हुई थी। लेकिन कोरोना के चलते साल 2020 में इन देशों के नेताओं की बैठक नहीं हो सकी थी। 2021 नवंबर में क्वाड में शामिल चारों देशों की नौसेना ने अरब सागर में अभ्यास किया था। क्वाड देशों की इस अभ्यास की वजह से चीन के माथे पर चिंता की लंकीरें आ गयी थीं। दरअसल, चीन को लगता था कि ये एक अमेरिका साजिश है जिसके जरिये चीन के अस्तित्व को बढ़ने से रोकने के कोशिश की जा रही है।

क्या है क्वाड

क्वाड यानी क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यह जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समझौता है। मूल तौर पर हिन्द प्रशांत क्षेत्र में काम कर रहा है। ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार आसान हो सके लेकिन अब यह व्यापार के साथ-साथ सैनिक बेस को मजबूती देने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सके।

बता दें कि 67 साले के शिंजो आबे को शुक्रवार यानी 8 जुलाई 2022 को पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक प्रचार भाषण के दौरान पीछे से गोली मार दी गयी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी धड़कन भी बंद हो चुकी थी। बाद में अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। जापान की पुलिस ने आबे के हत्या के आरोपी नारा शहर निवासी 41 साल के तेत्सुया यामागामी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि स्वास्थ्य कारणों को लेकर शिंजो आबे ने 2020 में जापान के प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था।

भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने कहा कि शिंजो आवे की हत्या बाद हमारा देश जापान के लोगों के साथ खड़ा है। जापान के साथ क्वाड बनाने वाले देशों में शामिल, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेताओं ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या पर आश्चर्य जता है। साथ ही कहा कि शिंजो आबे ने क्वाड देशों के बीच साझेदारी की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा आबे ने शांतिपूर्ण, समृद्ध हिन्द-प्रशांत की दिशा में भी अथक प्रयास किये।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बयान में कहा कि हम, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आवे की दुखद हत्या से स्तब्ध हैं।

तीनों देशों के नेताओं ने कहा कि शिंजो आवे एक परिवर्तनकारी नेता थे। उन्हीं के प्रयासों से हमारे देशों के संबंध जापान से बेहतर और मजबूत बने हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि शिंजो आबे ने कवाड की स्थापना में भी एक रचनात्मक भूमिका निभाई थी।

ऑब्जर्वर डॉन की टीम शिंजो आवे को श्रद्धांजलि देती है और श्रद्धा के पुष्प समर्पित करती है। अलविदा शिंजो आवे, आप बहुत याद आएंगे।

काकोरी कांड

जिसने देश में क्रांतिकारियों के प्रति जनता का नजरिया बदल दिया था



नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड का मुकदमा 10 महीने तक चला था जिसमें रामप्रसाद 'बिस्मिल', राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा हुई

गायत्री आर्य

भारत के स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र सुनने को नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि इतिहासकारों ने काकोरी



भारत के स्वाधीनता आंदोलन में काकोरी कांड की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र सुनने को नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि इतिहासकारों ने काकोरी कांड को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी।



भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर शोध करने वाली डॉ। रश्मि कुमारी लिखती हैं, '1857 की क्रांति के बाद उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में चापेकर बंधुओं द्वारा आर्यस्ट व रैंड की हत्या के साथ सैन्यवादी राष्ट्रवाद का जो दौर प्रारंभ हुआ, वह भारत के राष्ट्रीय फलक पर महात्मा गांधी के आगमन तक निर्विरोध जारी रहा। लेकिन फरवरी 1922 में चौरा-चौरी कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तब भारत के युवा वर्ग में जो निराशा उत्पन्न हुई उसका निराकरण काकोरी कांड ने ही किया था'।

1922 में जब देश में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उसी साल फरवरी में 'चौरा-चौरी कांड' हुआ। गोरखपुर जिले के चौरा-चौरी में भड़के हुए कुछ आंदोलकारियों ने एक थाने को घेरकर आग लगा दी थी जिसमें 22-23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस हिंसक घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिससे पूरे देश में जबरदस्त निराशा का माहौल छा गया था।

आजादी के इतिहास में असहयोग आंदोलन के बाद काकोरी कांड को एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि इसके बाद आम जनता अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए क्रांतिकारियों की तरफ और भी ज्यादा उम्मीद से देखने लगी थी।

नौ अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को 'काकोरी कांड' के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन 'हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन' (एचआरए) के सदस्य थे।

एचआरए की स्थापना 1923 में शचीन्द्रनाथ सान्याल ने की थी। इस क्रांतिकारी पार्टी के लोग अपने कामों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से डाके डालते थे। इन डकैतियों में धन कम मिलता था और निर्दोष व्यक्ति मारे जाते थे। इस कारण सरकार क्रांतिकारियों को चोर-डाकू कहकर बदनाम करती थी। धीरे-धीरे क्रांतिकारियों ने अपनी लूट की रणनीति बदली और सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई। काकोरी ट्रेन की डकैती इसी दिशा में क्रांतिकारियों का पहला बड़ा प्रयास था।

बताते हैं कि काकोरी षडयंत्र के संबंध में जब एचआरए दल की बैठक हुई तो अशफाक उल्लाह खां ने ट्रेन डकैती का विरोध करते हुए कहा, 'इस डकैती से हम सरकार को चुनौती तो अवश्य दे देंगे, परंतु यहीं से पार्टी का अंत प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि दल इतना सुसंगठित और दृढ़ नहीं है इसलिए अभी सरकार से सीधा मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा।' लेकिन अंततः काकोरी में ट्रेन में डकैती डालने की योजना बहुमत से पास हो गई।

कांड को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि काकोरी कांड ही वह घटना थी जिसके बाद देश में क्रांतिकारियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा था और वे पहले से ज्यादा लोकप्रिय होने लगे थे।

इस ट्रेन डकैती में कुल 4601 रुपये लूटे गए थे। इस लूट का विवरण देते हुए लखनऊ के पुलिस कप्तान मि. इंग्लिश ने 11 अगस्त 1925 को कहा, 'डकैत (क्रांतिकारी) खाकी कमीज और हाफ पैंट पहने हुए थे। उनकी संख्या 25 थी। यह सब पढ़े-लिखे लग रहे थे। पिस्तौल में जो कारतूस मिले थे, वे वैसे ही थे जैसे बंगाल की राजनीतिक क्रांतिकारी घटनाओं में प्रयुक्त किए गए थे।'

इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुई। हालांकि काकोरी ट्रेन डकैती में 10 आदमी ही शामिल थे, लेकिन 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजों की इस धरपकड़ से प्रांत में काफी हलचल मच गई। जवाहरलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि बड़े-बड़े लोगों ने जेल में क्रांतिकारियों से मुलाकात की और मुकदमा लड़ने में दिलचस्पी दिखाई। वे चाहते थे कि उनका मुकदमा सुप्रसिद्ध वकील गोविंद वल्लभ पंत लडें.। लेकिन उनकी फीस ज्यादा होने के कारण अंततः यह मुकदमा कलकत्ता के बीके चौधरी ने लड़ा।

काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थियेटर में चला (आजकल इस भवन में लखनऊ का प्रधान डाकघर है।)। इस पर सरकार का 10 लाख रुपये खर्च हुआ। छह अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें जज हेमिल्टन ने धारा 121अ, 120ब, और 396 के तहत क्रांतिकारियों को सजाएं सुनाईं। इस मुकदमे में रामप्रसाद 'बिस्मिल', राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई। शचीन्द्रनाथ सान्याल को कालेपानी और मन्मथनाथ गुप्त को 14 साल की सजा हुई।

योगेशचंद्र चटर्जी, मुकंदीलाल जी, गोविन्द चरणकर, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजा हुई। विष्णुशरण दुब्लिश और सुरेशचंद्र भट्टाचार्य को सात और भूपेन्द्रनाथ, रामदुलारे त्रिवेदी और प्रेमकिशन खन्ना को पांच-पांच साल की सजा हुई।

फांसी की सजा की खबर सुनते ही जनता आंदोलन पर उतारू हो गई। अदालत के फैसले के खिलाफ शचीन्द्रनाथ सान्याल और भूपेन्द्रनाथ सान्याल के अलावा सभी ने लखनऊ चीफ कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले गांडा जेल में राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई। फांसी के कुछ दिनों पहले एक पत्र में उन्होंने अपने मित्र को लिखा था, 'मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यदि यह सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है तो मैं समझता हूं, हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, सबको अंतिम नमस्ते।'

19 दिसंबर, 1927 को पं। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उन्होंने अपनी माता को एक पत्र लिखकर देशवासियों के नाम संदेश भेजा और फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए जोर से 'भारत माता' और 'वंदेमातम' की जयकार करते रहे। चलते समय उन्होंने कहा -

मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे,
बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे।
जब तक कि तन में जान, रगों में लहू रहे
तेरा हो जिक्र या, तेरी ही जुस्तजू रहे।

फांसी के दरवाजे पर पहुंचकर बिस्मिल ने कहा, 'मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं।' और फिर फांसी के तख्ते पर खड़े होकर प्रार्थना और मंत्र का जाप करके वे फंदे पर झूल गए। गोरखपुर की जनता ने उनके शव को लेकर आदर के साथ शहर में घुमाया। उनकी अर्थी पर इत्र और फूल बरसाए। काकोरी कांड के तीसरे शहीद थे, ठाकुर रोशन सिंह जिन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई। उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखते हुए कहा था, 'हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो आदमी धर्मयुद्ध में प्राण देता है, उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वालों की।'

अशफाक उल्ला खां काकोरी कांड के चौथे शहीद थे। उन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई। वे बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ का बस्ता कंधे पर लटकाए हाजियों की भांति 'लवेक' कहते और कलाम पढ़ते फांसी के तख्ते पर गए। तख्ते का उन्होंने चुंबन किया और उपस्थित जनता से कहा, 'मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया, वह गलत है। खुदा के यहां मेरा इंसाफ होगा।' और फंदे पर झूल गए। उनका अंतिम गीत था -

तंग आकर हम भी उनके जुल्म
से बेदाद से
चल दिए सुए अदम जिंदाने
फैजाबाद से

19 दिसंबर को उनका पार्थिव शरीर मालगाड़ी से शाहजहांपुर ले जाते समय गाड़ी लखनऊ बालामऊ स्टेशन पर रुकी। जहां पर एक साहब सूट-बूट में गाड़ी के अंदर आए और कहा, 'हम शहीद-ए-आजम को देखना चाहते हैं।' उन्होंने पार्थिव शरीर के दर्शन किए और कहा, 'कफन बंद कर दो, मैं अभी आता हूं।' यह साहब कोई और नहीं चन्द्रशेखर आजाद थे। काकोरी कांड में अंग्रेजों ने चन्द्रशेखर आजाद को भी बहुत ढूंढ़ा। वे हुलिया बदल-बदल कर बहुत समय तक अंग्रेजों को धोखा देने में सफल होते रहे। अंततः 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों का सामना करते हुए वे अपनी ही गोली से शहीद हो गए।

बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 4.90% से बढ़कर 5.40% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा एटकचुकानी होगी।

Subscribe Now!

OBSERVER DAWN
Power of Thoughts













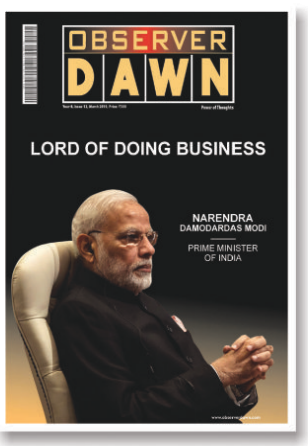



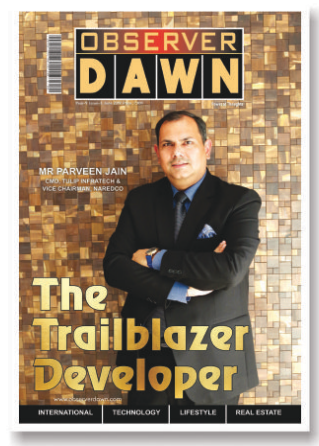

Contact us: 0120-4804768

Email: Info@observerdawn.com | *Website*: www.observerdawn.com

KW BLUE PEARL

The Rare Gem of Karol Bagh

KW GROUP
for touching heights

Delhi

High End Shopping Destination



Upto **649%** Growth of Investors in Last 10 Years

Ready for Possession

No GST | Immediate Registry | Completion Certificate Received
Main Road Corner Property | Entrance of Karol Bagh

Shops
₹50 Lacs

Rent Guarantee
₹42 Lacs

aarké RITU KUMAR | ethnix by Raymond | BARISTA | LOOKS UNISEX SALON

Call: 74-28-61-00-89

Site Office: B-2/6, Plot No.-2, Ashok Nagar, DB Gupta Road, Near Faiz Chowk, Karol Bagh, New, Delhi, 110005
Corp. Office: B-97, Sector-63, Noida, U.P. | **Tel:** 0120-4804747, | **Website:** www.kwbluepearl.com, kwgroup.in | **Email:** sales@kwgroup.in